वर्ष 13 • अंक 15 • 12 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

बुधवार 4 मार्च 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

चीनी निर्यात का लक्ष्य 80 फीसदी होगा पूरा

आदित्य मित्तल पृष्ठ 3

एस्सार की बिजली इकाई हासिल करने के करीब आर्सेलर-निप्पॉन

डॉलर रु. 73.30 ▲ 60 पैसे | यूरो रु. 81.40 ▲ 70 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 42276 ▲ 119 रुपये | सेंसेक्स 38623.70 ▲ 479.70 | निफ्टी 11303.30 ▲ 170.50 | निफ्टी फ्यूचर्स 11294.80 ▼ 08.50 | ब्रेंट क्रूड 53.10 डॉलर ▲ 0.40 डॉलर

एक नज़र

फेडरल रिजर्व ने दर में की 50 आधार अंक की कटौती

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने कोरोनावायरस के वैश्विक प्रसार को देखते हुए नीतिगत दरों में 50 आधार अंक की कटौती की है। बैंक की ओपन मार्केट कमेटी ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूती बन हुई है। लेकिन कोरोनावायरस के कारण आर्थिक गतिविधियों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है।

एजीआर पर नए नोटिस जारी करेगा दूरसंचार विभाग

दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान और सरकार द्वारा मांगी गई रकम में अंतर होने के कारण दूरसंचार विभाग इस सप्ताह उन्हें नया नोटिस जारी करेगा। इसके जरिये दूरसंचार कंपनियों से उनकी गणना के विस्तृत ब्योरे मांगे जाएंगे। भारती एयरटेल ने हाल ही में विभाग को 18,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और कहा था कि उसने एजीआर देनदारी मद में पूरी राशि का भुगतान कर दिया है। हालांकि विभाग के आकलन के अनुसार यह राशि 35,000 करोड़ रुपये है। वोडाफोन आइडिया ने 3,043 करोड़ रुपये के विलंबित स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान किया है जबकि टाटा टेलीसर्विसेज ने एजीआर बकाये का अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। पृष्ठ 2

एसबीआई काड्‌र्स को 87 फीसदी आवेदन

एसबीआई काड्‌र्स के आईपीओ को मंगलवार दूसरे दिन 87 फीसदी बोलियां मिलीं। मर्चेंट बैंकिंग सूत्रों के अनुसार खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित शेयर के खाते में 121 फीसदी आवेदन मिले जबकि पात्र संस्थागत खरीदारों के मामले में 21 फीसदी तथा गैर-संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 47 फीसदी बोलियां मिलीं। आईपीओ के लिए आवेदन मूल्य 750-755 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। आईपीओ गुरुवार को बंद होगा। पृष्ठ 3

अजय भूषण पांडेय बने वित्त सचिव

राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय को वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। वह राजीव कुमार की जगह लेंगे, जो सेवानिवृत्ति हुए हैं। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने महाराष्ट्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस अधिकारी पांडेय को वित्त सचिव मनोनीत किए जाने को मंजूरी दे दी है। पांडेय दिसंबर 2018 से ही वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। वित्त मंत्रालय के सचिवों में जो सबसे वरिष्ठ होते हैं, उन्हें वित्त सचिव मनोनीत किया जाता है।

ऑर्किड पर एनसीएलएटी का आदेश खारिज

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ऑर्किड फार्मा के लिए धानुका लैबोरेटरीज की समाधान योजना के खिलाफ दिए गए नैशनल कंपनी विधि अपील पंचाट (एनसीएलएटी) के आदेश को खारिज कर दिया। धानुका लैबोरेटरीज ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में ये बातें कही। भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर दिया गया आदेश एनसीएलटी में जून 2019 में मंजूरी की गई धानुका लैबोरेटरीज की समाधान योजना के लिए हरी झंडी है। नवंबर 2019 में एनसीएलएटी ने यह कहते हुए एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया था कि उसकी समाधान योजना परिसमापन कीमत से कम है और यह दिवालिया संहिता के प्रावधानों के खिलाफ है। पृष्ठ 3

वित्तीय बाजार को मिला भरोसा

कोरोना संकट के बीच वित्तीय बाजार को स्थायित्व देने की पहल करेगा आरबीआई

सुब्रत पांडा
मुंबई, 3 मार्च

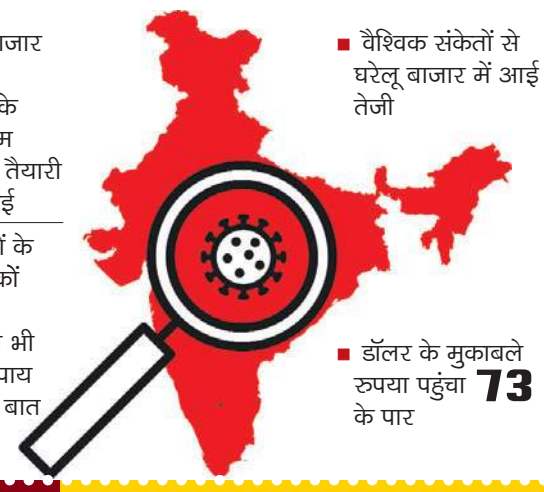

कोरोनावायरस की वजह से वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज कहा कि वह वित्तीय बाजार के सुचारू संचालन के लिए समुचित कदम उठाने के लिए तैयार है ताकि वित्तीय बाजार में स्थायित्व और भरोसा बहाल हो सके। इसके साथ ही आरबीआई वैश्विक और घरेलू घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है।

आरबीआई ने बयान में कहा, 'कोरोनावायरस की वजह से जोखिम बढ़ने के कारण दुनिया भर में वित्तीय बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। भारत में भी वित्तीय बाजार पर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक गतिविधियों पर इसके असर को कम करने के लिए नीतिगत कदमों से बाजार में भरोसा बढ़ा है।'

वैश्विक अनिश्चितता के बीच समन्वित कार्ययोजना बढ़ने के संकेत के तहत जी7 फाइनैंस और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों ने कोरोना के वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर को कम करने के उपाय तलाशने की खातिर बैठक की। बयान में कहा गया कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने सतत विकास और गिरावट के जोखिम से बचाव के लिए सभी समुचित नीतिगत उपाय करेंगे। जी7 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने आगे भी समय पर प्रभावी उपाय के लिए सहयोग करने की खातिर तत्पर रहने की बात कही।

वैश्विक संकेतों से चढ़ा बाजार

पिछले सात दिनों से गिरावट झेल रहे शेयर बाजार ने मंगलवार को तेजी दर्ज की। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा कोरोना की वजह से आर्थिक नुकसान को दुरुस्त करने की पहल से बाजार को करार मिला। अधिकांश एशियाई और यूरोपीय बाजारों में तेजी रही। सेंसेक्स भी 480 अंक चढ़कर 38,624 पर बंद हुआ। निफ्टी 170.6 अंक चढ़कर 11,303 पर बंद हुआ।

कोरोना के प्रसार से दुनिया भर के वित्तीय बाजारों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने वैश्विक समन्वय की संभावना के संकेत दिए थे। घरेलू और वैश्विक बाजारों पर इसका सकारात्मक असर हुआ। सेंसेक्स 480 अंक की बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी भी 170 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपये में नरमी बनी रही। रुपया 73 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर 73.29 पर बंद हुआ।

बैंकिंग नियामक द्वारा संभावित कदम उठाए जाने के बारे में भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी ने बताया कि बैंकिंग तंत्र में पर्याप्त नकदी है। हालांकि क्षेत्र विशेष के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करने की खातिर उपाय किए जा सकते हैं। कोरोना से प्रभावित इकाइयों और कंपनियों को कर्ज भुगतान में कुछ रियायत दी जा सकती है।

बाजार उत्सुकता से जी7 के केंद्रीय बैंकरों के कदम का इंतजार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि दर में कटौती होगी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक 17-18 मार्च को होगी लेकिन उससे पहले ही उसने मंगलवार को नीतिगत दर में 50 आधार अंक की कटौती की है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड सोशल एक्सीलेंस अवॉर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड सोशली अवेयर कॉरपोरेट
दीनानाथ दुभाषी
मुख्य कार्याधिकारी एलऐंडटी फाइनैंस होल्डिंग्स

बिज़नेस स्टैंडर्ड सोशल आंत्रप्रेन्योर
एमआर माधवन
अध्यक्ष, पीआरएस, लेजिस्लेटिव रिसर्च

बिज़नेस स्टैंडर्ड सोशल एंटरप्राइज
निहाल कविरत्ने
संस्थापक, सेंट ज्यूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर्स

गिवइंडिया के निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अतुल सतीजा, बेन कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के चेयरमैन अमित चंद्रा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफसोशल साइंसेज के चेयरमैन एस रामादुरई (निर्णायक मंडल के चेयरमैन), प्रथम की सह संस्थापक फरीदा लांबे और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक-निदेशक लुई मिरांडा (बाएं से दाएं)। फोटो : कमलेश पेडणेकर

सामाजिक सरोकारों को मिला सम्मान

बीएस संवाददाता
मुंबई, 3 मार्च

देश के ग्रामीण इलाकों में कैंसर प्रभावित बच्चों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाली श्रृंखला सेंट ज्यूड इंडिया चाइल्डकेयर सेंटर्स के संस्थापक निहाल कविरत्ने अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहते हैं, 'जब मेरी पत्नी श्यामा और मैं 22 साल तक विदेश में रहने के बाद भारत लौटे तो हम बच्चों के लिए इलाज मुहैया कराने की संभावनाएं देख रहे थे।'

गैर सरकारी संगठनों और अस्पतालों के कई चक्कर काटने और दोस्तों तथा परिजनों के साथ लंबी चर्चा के बाद कविरत्ने दंपती को कैंसर पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों की दुश्वारियों का पता चला। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए तो यह दोहरी मार थी। एक तो खतरनाक बीमारी और दूसरा इलाज और पोषण का अभाव। और फिर उनकी मदद के लिए आगे आया एक परोपकारी उद्यम, जिसे 2019 के बिज़नेस स्टैंडर्ड अवॉर्ड फॉर सोशल एंटरप्राइज के लिए चुना गया।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के चेयरमैन एस रामादुरई की अगुआई वाले पांच सदस्यीय निर्णायक मंडल ने सेंट ज्यूड इंडिया का चयन किया। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के संस्थापक एमआर माधवन को सोशल आंत्रप्रेन्योर और एलऐंडटी फाइनैंस होल्डिंग्स को सोशली अवेयर कॉरपोरेट का पुरस्कार मिला।

सभी विजेताओं ने कई मजबूत प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया। एलऐंडटी फाइनैंस होल्डिंग्स (एलटीएफएच) को ग्रामीण भारत में अपनी डिजिटल साक्षरता मुहिम डिजिटल साक्षी के लिए यह खिताब मिला।

(शेष पृष्ठ 12 पर)

स्थिति से निपटने को सरकार तैयार

एजेंसियां
नई दिल्ली, 3 मार्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनावायरस से निपटने की तैयारियों की आज व्यापक समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 नोवेल कोरोनावायरस से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालय और राज्य साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत आने वाले लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और संदिग्धों को त्वरित चिकित्सा उपचार मुहैया किया जा रहा है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें साथ मिलकर काम करने और आत्मसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे लेकिन अहम उपाय करने की जरूरत है।

इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि आगरा में जांच के दौरान 6 लोगों में तेज वायरल बुखार का पता चला है और उन्हें अलग रखा गया है। ये लोग दिल्ली के 45 साल के एक मरीज के संपर्क में आए थे। इस व्यक्ति में सोमवार को कोरोनावायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यह व्यक्ति आगरा में इन लोगों से मिला था। इनमें उसके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में अलग वार्ड में रखा गया है और उनके नमूनों को पुणे के राष्ट्रीय विषाणु संस्थान (एनआईवी) भेजा जा रहा है। समेकित बीमारी निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के जरिये उन लोगों का पता लगाया जा रहा है, जिनके संपर्क में ये छह लोग आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों के संदर्भ में पूर्व में जारी किए गए सभी परामर्शों के स्थान पर नया परामर्श जारी किया है। दिल्ली से सटे नोएडा के दो निजी स्कूलों ने अगले कुछ दिन के लिए अपने यहां कक्षाएं रद्द कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि मयूर विहार में रहने वाले संक्रमित व्यक्ति का बेटा इनमें से एक स्कूल में पढ़ता है। इसके कारण एहतियातन यह कदम उठाया गया है। दोनों स्कूलों ने अभिभावकों को संदेश भेजकर कक्षाएं रद्द होने की सूचना दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अधिकारियों के साथ कोरोनावायरस से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया।

कोरोनावायरस से संदिग्धों की जांच के लिए अस्पतालों में विशेष प्रबंध किए गए हैं।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोनावायरस नया संक्रमण है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हरसंभव कदम उठा रही है। 25 अस्पतालों में पृथक वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। तीन लाख पचास हजार एन-95 मास्क की व्यवस्था की गई है। कोरोनावायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज करने वाले कर्मचारियों के लिए अलग से 8,000 किट की व्यवस्था की गई है।

13 बल्क दवाओं के निर्यात पर रोक

कोरोनावायरस का प्रकोप दुनिया भर में फैलने और इससे मुख्य रूप से प्रभावित चीन से आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच भारत ने घरेलू बाजार में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 सक्रिय औषधि-निर्माण सामग्रियों (एपीआई) और उनसे बनी दवाओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि पैरासिटामॉल, टिनिडेजोल, विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एसिक्लोविर एवं प्रोगेस्टोरोन जैसी 13 एपीआई और इनसे बनने वाली दवाओं के निर्यात को सीमित करने का आदेश दिया है। पृष्ठ 12

जेपी इन्फ्रा के अधिग्रहण के लिए एनबीसीसी को मंजूरी

भाषा
नई दिल्ली, 3 मार्च

- **एनसीएलटी ने ऋणशोधन समाधान योजना के तहत दी मंजूरी**
- **20,000 फ्लैटों का निर्माण साढ़े तीन साल में करेगी एनबीसीसी**
- **जेपी द्वारा जमा कराए गए 700 करोड़ रुपये भी इस योजना में शामिल**

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) ने ऋण समाधान योजना के तहत कर्ज में डूबी जेपी इन्फ्राटेक को खरीदने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनबीसीसी के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। एनबीसीसी जेपी इन्फ्रा की अटकी परियोजनाओं में 20,000 फ्लैट को निर्माण साढे तीन साल में करेगी।

पंचाट के कार्यवाहक अध्यक्ष बीएस वी प्रकाश कुमार की अध्यक्षता वाले प्रधान पीठ ने एनबीसीसी द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को जेपी इन्फ्राटेक के ऋणदाताओं ने पिछले साल दिसंबर में ही मंजूरी दे दी थी। पंचाट ने यह भी आदेश दिया कि जेपी इन्फ्राटेक की मूल कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स द्वारा जमा 750 करोड़ रुपये इस योजना का हिस्सा होगा। यह पैसा उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री में जमा है। पीठ ने कहा कि 750 करोड़ रुपये का योजना का हिस्सा माना जाएगा।

लिखित आदेश बुधवार को उपलब्ध होगा। सफल समाधान योजना से जेपी इन्फ्राटेक की उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में फंसे 20,000 से अधिक मकान खरीदारों को राहत मिलेगी। जेपी इन्फ्राटेक का मामला अगस्त 2017 में ऋण शोधन प्रक्रिया में गया था।

जेपी इन्फ्रा के ऋणदाताओं की समिति ने पिछले साल दिसंबर में एनबीसीसी की समाधान योजना को मंजूरी दे दी थी। समिति में 13 बैंक और करीब 21,000 मकान खरीदार शामिल हैं।

महंगाई से जुड़ेगा कामगारों का वेतन

सोमेश झा
नई दिल्ली, 3 मार्च

औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 3 करोड़ कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होना तय लग रहा है। सरकार की एक उच्च स्तरीय समिति ने ऐसे कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा एक नया आधार तय किया है। सरकार की इस पहल से केंद्र सरकार के उन 48 लाख कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा, जिनका महंगाई भत्ता इस महंगाई सूचकांक से जुड़ा होगा।

मुख्य श्रम एवं रोजगार सलाहकार बी एन नंदा के नेतृत्व में एक त्रिपक्षीय समिति की 27 फरवरी को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक नई सीरीज के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) को मंजूरी दी गई थी। इसके लिए 2016 को आधार वर्ष बनाया गया था। 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए नंदा ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया,'इस निर्णय से देश में संगठित औद्योगिक 3 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इनके साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कर्मचारियों को भी फायदा होगा। सरकार की अनुमति मिलने के बाद महंगाई भत्ते में व्यापक बदलाव होगा।'

केंद्र सरकार एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हरेक छह महीने पर अद्यतन होता है। सातवें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई समायोजित करने के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू को आधार बनाया था। निजी क्षेत्र में कर्मचारी संघ भी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर बातचीत के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का सहारा लेते हैं। 2001 के बाद सीपीआई-आईडब्ल्यू में संशोधन नहीं हुआ है। आम तौर पर इसमें हरेक पांच वर्षों के बाद बदलाव होना चाहिए। सीपीआई का पुराना आधार मौजूदा गणना के अनुरूप नहीं है, क्योंकि पिछले दो दशकों में उपभोक्ता प्रारूप में खासा बदलाव आया है। महंगाई की गणना के लिए कुछ खास वस्तु एवं सेवाओं पर नजर रखी जाती है।

27 फरवरी को हुई बैठक में समिति को सौंपी गई प्रस्तुति के अनसुार 2016 आधार वर्ष के साथ सीपीआई-आईडब्ल्यू गैर-खाद्य वस्तुओं को अधिक तवज्जो देगा, जबकि 2001 के सूचकांक में खाद्य वस्तुओं को प्रमुखता दी जाती थी। नया सूचकांक विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 48,000 से अधिक कर्मचारी परिवारों का सर्वेक्षण किया था। नई सीरीज में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भारांश 46 प्रतिशत से कम होकर 39 प्रतिशत रह जाएगा। दूसरी तरफ, गैर-खाद्य वस्तुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन एवं पुनर्सृजन, घरेलू वस्तुएं एवं सेवाएं, परिवहन एवं संचार का भारांश 2016 सीरीज में 2001 के सूचकांक के 23 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो जाएगा।

मुद्रास्फीति के घटक*

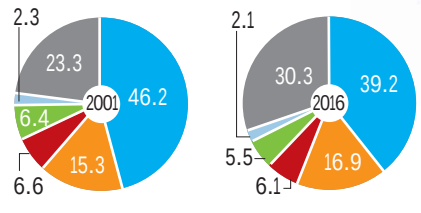

■ फूड एवं बेवरिजेज ■ हाउसिंग ■ कपड़े एवं जूते-चप्पल ■ ईंधन एवं बिजली ■ पान, सुपारी, तंबाकू और मादक पदार्थ ■ अन्य#

*खुदरा मुद्रास्फीति (आईडब्ल्यू) : औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
#शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, घरेलू वस्तुएं औ सेवाएं, परिवहन तथा संचार और पर्सनल केयर व अन्य
स्रोत : सीपीआई (आईडब्ल्यू) पर त्रिपक्षीय स्थायी समिति

खबरों में रहे स्टॉक

अल्ट्राटेक सीमेंट

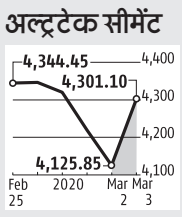

अगले वित्त वर्ष में कंपनी की लाभप्रदता दमदार रहने का अनुमान

₹ 4,125.85 पिछला बंद भाव
₹ 4,301.10 आज का बंद भाव
▲ 4.25 %

हीरो मोटोकॉर्प

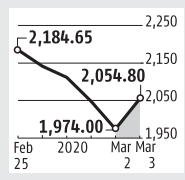

आपूर्ति जल्द सुचारू होने की उम्मीद

₹ 1,974.00 पिछला बंद भाव
₹ 2,054.80 आज का बंद भाव
▲ 4.09 %

सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज

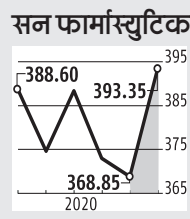

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स में सबसे अधिक चढ़ने वाला शेयर

₹ 368.85 पिछला बंद भाव
₹ 393.35 आज का बंद भाव
▲ 6.64 %

आयशर मोटर्स

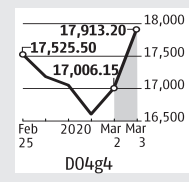

फरवरी में बिक्री 1 फीसदी बढ़ी

₹ 17,006.15 पिछला बंद भाव
₹ 17,913.20 आज का बंद भाव
▲ 5.33 %

टाटा एलेक्सी

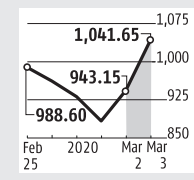

रुपये के 73 पार जाने से चढ़े आईटी शेयर

₹ 943.15 पिछला बंद भाव
₹ 1,041.65 आज का बंद भाव
▲ 10.44 %

संक्षेप में

तीन कंपनियों को मिली आईपीओ की मंजूरी

होम फर्स्ट फाइनैंस, इंडियन रेलवे फाइनैंस कॉरपोरेशन और इक्विटास स्मॉल फाइनैंस बैंक को बाजार नियामक सेबी से अपना-अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम पेश करने की मंजूरी मिल गई है। तीनों आईपीओ वित्तीय क्षेत्र के हैं और इनमें प्राथमिक व द्वितीयक बिक्री शामिल होगी। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि अपनी शेयर बिक्री के लिए कंपनियां द्वितीयक बाजार में हो रहे उतारचढ़ाव पर विराम लगने तक इंतजार कर सकती हैं। *बीएस*

एंटनी वेस्ट ने एंकर निवेशकों से जुटाई रकम

एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल ने अपने आईपीओ से पहले तीन एंकर निवेशकों को 61 करोड़ रुपये के शेयर आवंटित किए हैं। इन निवेशकों में माशासुचेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वांटेज इक्विटी फंड और 238 प्लान एसोसिएट्स शामिल है। वेस्ट मैनेजमेंट फर्म का 200 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार को खुलेगा और शुक्रवार को बंद होगा। इस शेयर बिक्री में 35 करोड़ रुपये नए शेयर से जुटाए जाएंगे जबकि 171 करोड़ रुपये द्वितीयक शेयर बिक्री के जरिये। इक्विरस कैपिटल इस आईपीओ का कामकाज संभालने के लिए निवेश बैंकर है। *बीएस*

एजीआर: नए नोटिस की तैयारी

दूरसंचार कंपनियों से एजीआर संबंधी बकाये की गणना का ब्योरा मांगेगा विभाग

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 3 मार्च

दूरसंचार कंपनियों द्वारा किए गए भुगतान और सरकार द्वारा मांगी गई रकम में अंतर होने के कारण दूरसंचार विभाग इसी सप्ताह दूरसंचार कंपनियों को एक नया नोटिस जारी करेगा। इसके जरिये दूरसंचार कंपनियों से उनकी गणना के विस्तृत ब्योरे मांगे जाएंगे।

दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'दूरसंचार कंपनियों से हमें अब तक 24,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं जो हमारे आकलन के अनुसार काफी कम है। वे हमें बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार गणना की और यह नतीजा निकाला।'

भारती एयरटेल ने 29 फरवरी को कहा था कि उसने सरकार के बकाये सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) संबंधी गणना पूरी कर ली है। कंपनी द्वारा खुद किए गए आकलन के तहत बकाया रकम 13,004 करोड़ रुपये है जिसका भुगतान वह पहले ही कर चुकी है।

सरकार के आकलन के अनुसार, सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाली इस कंपनी पर दूरसंचार विभाग का बकाया 35,500 करोड़ रुपये है।

एजीआर बकाया

- दूरसंचार कंपनियों से सरकार को एजीआर बकाये के तौर पर अब तक मिले 24,000 करोड़ रुपये
- भारती एयरटेल कुल 13,004 करोड़ रुपये भुगतान कर चुकी है
- टाटा समूह ने एजीआर बकाये के निपटान के तहत 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया है

बकाये का यह आकलन 2006-07 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए किया गया था।

भारती एयरटेल ने इस महीने के आरंभ में दूरसंचार विभाग को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया था और शेष 3,004 करोड़ रुपये का भी भुगतान किया जा चुका है। इसके साथ ही कंपनी ने कहा है कि उसने अक्टूबर में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुरूप पिछले 14 वर्षों के एजीआर संबंधी बकाये का भुगतान कर दिया है।

भारती एयरटेल ने 13,004 करोड़ रुपये के अलावा अस्थायी भुगतान के तौर पर 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान भी किया है ताकि सुलह प्रक्रिया के दौरान दूरसंचार विभाग की मांग में अंतर को पूरा किया जा सके।

भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज और वोडाफोन आइडिया द्वारा आंशिक भुगतान किए जाने के बावजूद दूरसंचार विभाग ने पिछले सप्ताह सभी ऑपरेटरों को एजीआर बकाये का खुद आकलन करने का निर्देश दिया था।

सरकार दूरसंचार कंपनियों पर एजीआर बकाये के मामले को निपटाने के लिए किसी ऑडिट फर्म को तीसरे पक्ष के तौर पर नियुक्त करने की संभावनाएं तलाश रही है। इससे दोनों पक्षों की गणना में अंतर को दूर करने में मदद मिलेगी। मिंट ने 21 फरवरी को ऐसी खबर दी थी।

उधर, टाटा समूह ने सरकार को दूरसंचार क्षेत्र के अपने कारोबार पर समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाये के निपटान के तहत 2,000 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त भुगतान तदर्थ आधार पर किया है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्र ने कहा कि टाटा समूह सरकार को पहले ही 2,197 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। यह तदर्थ 2,000 करोड़ रुपए का भुगतान उसके अतिरिक्त है। दूरसंचार विभाग के आकलन के अनुसार टाटा समूह पर सांविधिक बकाए के करीब 14,000 करोड़ रुपये बनते हैं।

अब जोमैटो की हुई उबर ईट्स इंडिया

नेहा अलावधी
नई दिल्ली, 3 मार्च

उबर ने अपने भारतीय फूड डिलिवरी कारोबार को 20.6 करोड़ डॉलर के एक सौदे के तहत जोमैटो को बेच दिया है। अमेरिकी कंपनी ने सोमवार को यूएस सिक्योरिटी ऐंड एक्सचेंज कमीशन को सौंपी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है।

उबर ने कहा, 'इस सौदे का उचित अनुमानित मूल्य 20.6 करोड़ डॉलर है जिसमें 17.1 करोड़ डॉलर का निवेश मूल्य और वस्तु एवं सेवा कर के लिए जोमैटो से प्राप्त 3.5 करोड़ डॉलर की प्रतिपूर्ति शामिल हैं।'

इस सौदे की घोषणा 21 जनवरी को की गई थी। इसके तहत उबर को जोमैटो में 9.9 फीसदी हिस्सेदारी मिलेगी। उस समय इस सौदे का मूल्य 35 से 40 करोड़ डॉलर आंका गया था। कंपनी ने बिक्री का खुलासा नहीं किया है क्योंकि उसका परिचालन बाधित रहा था और माना गया था कि यह कुल कारोबार का एक मामूली हिस्सा है।

उबर ने एक रिपोर्ट में कहा है, 'उबर ईट्स इंडिया की बिक्री ऐसा कोई रणनीतिक बदलाव नहीं है जिसका कंपनी के परिचालन एवं वित्तीय नतीजों पर कोई बड़ा प्रभाव दिखे। इसलिए बाधित कारोबार के तौर पर उसे वित्तीय नतीजे में शामिल नहीं किया गया है। कंपनी के उबर ईट्स इंडिया की की कुल परिसंपत्ति एवं देनदारी 31 दिसंबर 2019 अगल से खुलासा करने के योग्य नहीं थी क्योंकि उसे समेकित बहीखाते पर बिक्री के रूप में दर्शाया गया है।'

- उबर ने 20.6 करोड़ डॉलर के एक सौदे के तहत की बिक्री
- इसमें 17.1 करोड़ डॉलर का निवेश मूल्य और वस्तु एवं सेवा कर के लिए जोमैटो से प्राप्त 3.5 करोड़ डॉलर की प्रतिपूर्ति शामिल

उबर ने करीब चार साल पहले वैश्विक स्तर पर अपने ईट्स कारोबार की शुरुआत की थी। कंपनी के अनुसार, 31 दिसंबर 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ईट्स की कुल बुकिंग 83 फीसदी बढ़कर अथवा स्थिर मुद्रा पर 87 फीसदी बढ़कर 6.6 अरब डॉलर से 14.5 अरब डॉलर हो गई। जबकि उसके राजस्व में 72 फीसदी और स्थिर मुद्रा पर 76 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई।

बीसी त्रिपाठी बने एस्सार एक्सप्लोरेशन ऐंड प्रोडक्शन मारीशस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

गेल इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भुवन चंद्र त्रिपाठी रुइया-परिवार के स्वामित्व वाली एस्सार समूह की मॉरीशस स्थित तेल एवं गैस कंपनी में गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। कंपनी ने कहा, एस्सार ग्लोबल फंड लिमिटेड के निवेश प्रबंधक एस्सार कैपिटल लिमिटेड ने त्रिपाठी को एस्सार एक्सप्लोरेशन ऐंड प्रोडक्शन लिमिटेड मॉरीशस (ईईपीएलएम) का गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और एस्सार ऑयल यूके लिमिटेड (ईओयूकेएल) के निदेशक मंडल का सदस्य नियुक्त किया है। *भाषा*

ईटीएफ का घटा निवेश

समी मोडक
मुंबई, 3 मार्च

उभरते बाजारों (ईएम) में निवेश करने वाले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के निवेश प्रवाह में पिछले सप्ताह जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। कई वैश्विक बाजारों में 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद सबसे बड़ा साप्ताहिक झटका लगा।

एमएससीआई ईएम सूचकांक में पिछले सप्ताह 7.2 फीसदी की गिरावट आई। अर्थव्यवस्था और कंपनियों की आय पर कोरोनावायरस के प्रभाव के मद्देनजर निवेशकों ने अधिक जोखिम वाली परिसंपत्तियों में बिकवाली शुरू कर दी जिससे इस सूचकांक को झटका लगा।

ब्लूमबर्ग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, उभरते बाजारों के शेयर और बॉन्ड खरीदने वाले अमेरिका में सूचीबद्ध ईटीएफ से करीब 37.3 लाख डॉलर भुना लिए गए जो पिछले करीब एक साल के दौरान सर्वाधिक है। इसमें से करीब 34 लाख डॉलर शेयर बाजार से भुनाए गए।

हॉन्ग कॉन्ग में सूचीबद्ध चीन के शेयरों में निवेश करने वाले ईटीएफ का निवेश प्रवाह करीब 1.4 अरब डॉलर रहा जो उभरते बाजारों में सर्वाधिक है। भारतीय बाजार इस लिहाज से दूसरे पायदान पर है जहां 41.6 करोड़ डॉलर का निवेश हुआ जो पिछली गिरावट के मुकाबले 18 गुना अधिक है।

अमेरिका में सूचीबद्ध ईएम ईटीएफ विदेशी निवेशकों एक श्रेणी है जो घरेलू बाजार में निवेश करती है। इसके अलावा घरेलू ईटीएफ और अमेरिका के बाहर सूचीबद्ध ईटीएफ भी हैं। इसके अलावा सक्रियता से प्रबंधित फंड भी हैं जो प्रबंधकों के विवेक के अनुसार विभिन्न बाजारों में निवेश करते हैं।

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीओ) द्वारा घरेलू बाजार से निकासी की कुल रकम करीब 1.8 अरब डॉलर है। इसलिए निकासी की करीब एक चौथाई रकम अमेरिकी ईएम ईटीएफ से संबंधित है।

बाजार प्रतिभागियों का कहना है कि वैश्विक ईटीएफ अब बाजार को काफी प्रभावित करने लगा है। कोरोनावायरस के उजागर होने से पहले ईएम ईटीएफ का जबरदस्त निदेश दिख रहा था। इससे कमजोर आर्थिक परिदृश्य और तीसरी तिमाही के कमजोर वित्तीय नतीजे के बावजूद मध्य जनवरी में घरेलू बाजार को नई ऊंचाई तक जाने में मदद मिली।

आईपीओ लाने की तैयारी कर रही ओला

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 3 मार्च

सॉफ्टबैंक के निवेश वाली राइड-हेलिंग कंपनी ओला अगले कुछ वर्षों में अपने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के साथ पूंजी बाजार में उतरने की योजना बना रही है।

ओला के सह-संस्थापक एवं सीईओ भाविश अग्रवाल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कंपनी हमेशा से एक टिकाऊ, आत्मनिर्भर, लाभप्रद और दीर्घावधि संस्थान बनने पर ध्यान केंद्रित करती रही है।

पुणे में आयोजित एमईए-पीआईसी जियो-इकनॉमिक कॉन्फ्रेंस के दौरान अग्रवाल ने कहा, 'हमारा भारतीय कारोबार एक मजबूत स्थिति में है और हम अन्य देशों में भी उसे दोहराना चाहते हैं। हमारे लिए अगला तार्किक कदम शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराना है। हम अपने विदेशी प्रतिस्पर्धियों के विपरीत भारतीय मूल के हैं और इसलिए हम भारत में सूचीबद्ध होंगे।' उन्होंने कहा, 'एक भारतीय कंपनी के तौर पर भारत में सूचीबद्ध होना हमारे लिए काफी महत्त्वपूर्ण है। हो सकता है कि हमें देखकर कुछ अन्य भारतीय इंटरनेट कंपनी भी निजी बाजारों पर भरोसा करने के बजाय आईपीओ की ओर रुख कर दे।'

बेंगलूरु की यह कंपनी अमेरिका की दिग्गज कंपनी उबर को टक्कर देती है। पिछले साल उबर के आईपीओ को कम मूल्यांकन के मद्देनजर निवेशकों से अधिक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी। सॉफ्टबैंक के निवेश वाली कंपनी वीवर्क ने अमेरिका में कंपनी के आईपीओ को आगे बढ़ाया क्योंकि निवेशकों ने 47 अरब डॉलर पर सवाल उठाए थे।

ओला ने वित्त पोषण के जरिये करीब 3.8 अरब डॉलर जुटाए हैं और उसका मूल्यांकन करीब 5.8 अरब डॉलर है।

कंपनियों का डिजिटलीकरण पर जोर

पवन लाल
मुंबई, 3 मार्च

बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 50 कंपनियों में से करीब एक तिहाई से अधिक कंपनियों ने डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया पूरी कर ली है। मैकिंजी ऐंड कंपनी की एक रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। मैकिंजी डिजिटल के पार्टनर और भारत में मैकिंजी एनालिटिक्स प्रैक्टिसेज के लीडर कुश बहल ने कहा कि करीब 32 फीसदी कंपनियों में परिणाम दिखने लगे हैं जबकि 42 फीसदी ने बदलाव की प्रक्रिया तो शुरू की लेकिन फिलहाल कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं दिखा है। उन्होंने कहा कि शेष 26 फीसदी कंपनियां अभी शुरुआती स्थिति में हैं।

हालांकि डिजिटल बदलाव के सफल होने की राह में प्रमुख बाधाओं में सही संगठनात्मक दृष्टिकोण, विभिन्न गतिविधियों के लिए ढांचे का निर्माण, लोगों के बीच दक्षता का सृजन और नजरिये में बदलाव शामिल हैं। लेकिन डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संगठन के भीतर 'बदलाव कार्यालय' के तहत एक कार्यकारी पद सृजित करने की भी जरूरत है। उस बदलाव कार्यालय की कमान एक मुख्य बदलाव अधिकारी के पास होगी जो मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक होंगे और वह मुख्य डेटा अधिकारी (सीडीओ) के तौर पर सभी तरह की डिजिटल पहल पर नजर रखते हैं। सीडीओ ही संसाधन जुटाते हैं अथवा एक मुख्य डिजिटल अधिकारी सपोर्ट ऐंड सर्विस मुहैया कराने वाले स्टार्टअप एवं अन्य तकनीकी वेंडरों के साथ मिलकर को संगठन को खड़ा करते हैं।

- शीर्ष 50 सूचीबद्ध कंपनियों में 30 फीसदी से अधिक का पूरा हुआ डिजिटल बदलाव
- करीब 32 फीसदी कंपनियों में परिणाम दिखने लगे हैं जबकि 42 फीसदी ने बदलाव की प्रक्रिया तो शुरू की लेकिन फिलहाल कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं दिखा है
- शेष 26 फीसदी कंपनियां अभी शुरुआती स्थिति में

डिजिटल बदलाव की ओर तेजी से आगे बढ़ने वाले उद्योगों में वित्तीय सेवा, वाहन, दूरसंचार और कुछ हद तक विनिर्माण शामिल हैं। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अधिकारियों ने कहा है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म योनो पूरी तरह ई-कॉमर्स कंपनियों के इतर सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है।

एसबीआई के पास करीब 100 साझेदार हैं और वह एमेजॉन, फ्लिपकार्ट एवं आईआरसीटीसी के साथ बड़ी तादाद में लेनदेन से संबंधित है। डिजिटल बदलाव का एक अन्य उदाहरण टाटा स्टील है जिसे हाल में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ग्लोबल लाइटहाउस नेटवर्क में शामिल किया गया है। डिजिटल एवं एनालिटिक्स समाधान में निवेश के कारण टाटा स्टील के कलिंगनगर संयंत्र के विपणन समय में 50 फीसदी का सुधार हुआ है। साथ ही डिजिटल कौशल वाले कनिष्ठ संसाधन तैयार करने के लिए क्षमता का भी निर्माण होगा।

हाल में वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली कंपनी अशोक लीलैंड ने 60,000 करोड़ रुपये के सर्विसिंग बाजार को भुनाने के लिए डिजिटल को एक महत्त्वपूर्ण रणनीति के तौर पर पहचान की है। मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) द्वारा परिचालित गैरेज और सर्विस स्टेशन के बीच दूरी आमतौर पर 100 किलोमीटर होती है जबकि स्थानीय गैरेज के साथ वह दूरी महज 3 किलोमीटर होती है। कंपनी ने अपनी डिजिटल पहल के लिए 20,000 मशीनों की मैपिंग की है।

एस्सार की सहायक इकाई हासिल करने के करीब आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील

ईशिता आयान दत्त
कोलकाता, 3 मार्च

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) एस्सार की सहायक इकाई को हासिल करने के करीब पहुंच गई है, जो एस्सार स्टील के अधिग्रहण का हिस्सा नहीं है।

मंगलवार को आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने ऐलान किया है कि उसने एडलवाइस रीकंस्ट्रक्शन कंपनी से भांडेर पावर प्लांट हजीरा (गुजरात) का अधिग्रहण पूरा कर लिया। भांडेर प्लांट की स्थापित क्षमता 500 मेगावॉट है और यह आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के हजीरा स्टील विनिर्माण के लिए कैप्टिव संयंत्र बना रहेगा। कंपनी ने आज यह जानकारी दी।

भांडेर संयंत्र 2006 में चालू हुआ था और वाणिज्यिक परिचालन 2008 में हुआ। हाल तक इसका स्वामित्व एस्सार समूह के प्रवर्तकों रुइया के पास था, जिन्होंने उसे 475 करोड़ रुपये में एडलवाइस को बेच दिया था। आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने सरफेसी अधिनियम के तहत इस बिजली संयंत्र को खरीदा है।

भांडेर पावर प्लांट का अधिग्रहण आर्सेलरमित्तल की तरफ से ओडिशा स्लरी पाइपलाइन के अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी के आदेश के आसपास हो रहा है। सोमवार को एनसीएलटी के कटक पीठ ने आर्सेलरमित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ओडिशा स्लरी पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए 2,359 करोड़ रुपये के समाधान योजना को मंजूरी दे दी।

आर्सेलरमित्तल के प्रवक्ता ने कहा, हम एनसीएलटी के कटक पीठ के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसने ओडिशा स्लरी पाइपलाइन के लिए हमारी समाधान योजना को मंजूरी दे दी, जिसे पहले लेनदारों की समिति ने आमसहमति से मंजूर कर लिया था। 253 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के लिए अहम इकाई है। यह पाइपलाइन आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को डबुना संयंत्र को ओडिशा में उसके पारादीप स्थित पैलेट संयंत्र से जोड़ती है। एनसीएलटी में आज की मंजूरी के बाद हम बाकी औपचारिका पूरी करेंगे, जिससे परिसंपत्तियां आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को हस्तांतरित हो जाएंगी।

सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से 42,000 करोड़ रुपये में एस्सार स्टील के अधिग्रहण की मंजूरी दिए जाने के बाद दिसंबर में ओडिशा स्लरी पाइपलाइन की लेनदारों की समिति ने आर्सेलरमित्तल की अग्रिम भुगतान की पेशकश को चुना था। हालांकि उसकी समाधान योजना को प्रतिस्पधी बोलीदाता त्रिवेणी अर्थमूवर्स और श्रेय इन्फ्रा फाइनैंस ने चुनौती दी थी। सूत्रों ने कहा कि पिछले हफ्ते त्रिवेणी ने एनसीएलटी से आवेदन वापस ले लिया और अंतत: आर्सेलरमित्तल की समाधान योजना मंजूर हो गई।

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने हालांकि सहायक इकाइयों मसलने स्लरी पाइपलाइन व बिजली संयंत्र का अधिग्रहण किया है, लेकिन कैप्टिव पोर्ट अभी भी एस्सार समूह के प्रवर्तकों के नियंत्रण में है।

हालांकि कैप्टिव कच्चे माल के लिए भी कदम उठाए गए हैं। इस महीने एएमआईपीएल को ओडिशा में लौह अयस्क खदान के लाइसेंस की खातिर तरजीही बोलीदाता चुना गया और इससे पहले राज्य सरकार ने नीलामी आयोजित की।

क्योंझर जिले में ठकुरानी ब्लॉक में अनुमानित तौर पर 17.90 करोड़ टन का भंडार है और यह आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया की लंबी अवधि की कच्चे माल की जरूरत में योगदान कर सकता है।

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के सीईओ दिलीप ओमेन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, अपने स्टील निर्माण संयंत्रों के लिए अहम सहायक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से हम खुश हैं।

आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील के बढ़ते कदम

- आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने एडलवाइस रीकंस्ट्रक्शन कंपनी से भांडेर पावर प्लांट हजीरा (गुजरात) का अधिग्रहण पूरा कर लिया
- हाल तक इसका स्वामित्व एस्सार समूह के प्रवर्तकों रुइया के पास था, जिन्होंने उसे 475 करोड़ रुपये में एडलवाइस को बेच दिया था
- भांडेर पावर प्लांट का अधिग्रहण आर्सेलरमित्तल की तरफ से ओडिशा स्लरी पाइपलाइन के अधिग्रहण के लिए एनसीएलटी के आदेश के आसपास हो रहा है

ऑर्किड फार्मा की समाधान योजना पर एनसीएलएटी का आदेश खारिज

गिरीश बाबू
चेन्नई, 3 मार्च

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में ऑर्किड फार्मा के लिए धानुका लैबोरेटरीज की समाधान योजना के खिलाफ दिए गए नैशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेश को खारिज कर दिया। धानुका लैबोरेटरीज ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में ये बातें कही।

भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर दिया गया आदेश एनसीएलटी में जून 2019 में मंजूरी की गई धानुका लैबोरेटरीज की समाधान योजना के लिए हरी झंडी है। कानूनी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

नवंबर 2019 में एनसीएलएटी ने यह कहते हुए एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया था कि उसकी समाधान योजना परिसमापन कीमत से कम है और यह दिवालिया संहिता के प्रावधानों के खिलाफ है। इसके अलावा यह कॉरपोरेट कर्जदाता की परिसंपत्तियों से मिलने वाली रकम को अधिकतम करने के सिद्धांत के खिलाफ भी है। एनसीएलएटी ने एकॉर्ड लाइफ की याचिका पर आदेश देते हुए ये बातें कही थी। एकॉर्ड लाइफ, ऑर्किड फार्मा के लिए नाकाम बोलीदाता थी।

सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ ने कहा कि एनसीएलएटी के आदेश को हालिया फैसले के आलोक में खारिज किया गया, जहां विशेष तौर पर कहा गया था कि दिवालिया संहिता का ऐसा कोई प्रावधान अदालत की जानकारी में नहीं लाया गया, जिसके तहत समाधान आवेदक को परिसमापन कीमत के बराबर बोली लगानी जरूरी हो। इसके मुताबिक अपील की अनुमति दी गई और एनसीएलएटी के फैसले को खारिज किया गया।

लेनदारों की समिति में शामिल एसबीआई ने यह आरोप लगाते हुए एनसीएलएटी के खिलाफ अपील की कि ट्रिब्यूल ने सीओसी की वाणिज्यिक समझ से ऊपर फैसला दिया। यह ऑर्किड फार्मा के निवेशकों को बचाने की दूसरी कोशिश है। इससे पहले एनसीएलटी ने अमेरिकी कंपनी इंजेन कैपिटल की समाधान योजना को अमान्य घोषित कर दिया था क्योंकि निवेशक कथित तौर पर नियम के मुताबिक रकम नहीं ला पाए।

ऑर्किड फार्मा पर 24 बैंकों का करीब 3,200 करोड़ रुपये बकाया है। एकॉर्ड का आरोप था कि धानुका की वास्तविक समाधान योजना 570 करोड़ रुये की थी जबकि परिसमापन कीमत 1,309 करोड़ रुपये थी।

एनसीएलटी ने कहा कि रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के मुताबिक, एक और जहां धानुका की 570 करोड़ रुपये की समाधान योजना परिसमापन कीमत से कम थी, वहीं ऑर्किड फार्मा का नकद व बैंक शेष 321.98 करोड़ रुपये का था।

- अपील ट्रिब्यूनल ने धानुका लैबोरेटरीज की समाधान योजना को खारिज कर दिया था
- भारतीय स्टेट बैंक की अपील पर दिया गया आदेश धानुका लैबोरेटरीज की समाधान योजना के लिए हरी झंडी है।

रिलायंस कैपिटल, होम फाइनैंस ने की कर्ज भुगतान में चूक

अभिजित लेले
मुंबई, 3 मार्च

रिलायंस कैपिटल लिमिटेड ने एचडीएफसी को 4.76 करोड़ रुपये के ब्याज भुगतान में चूक की है जबकि ऐक्सिस के सावधि कर्ज पर 0.71 करोड़ रुरुपये के भुगतान पर। कंपनी 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज चुकाने में नाकाम रही।

कर्ज व ब्याज भुगतान में देरी 20 नवंबर 2019 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के कारण हो रही है, जिसमें संपत्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेचने आदि पर रोक लगी हुई है। कंपनी ने बीएसई को भेजी सूचना में ये बातें कही।

साथ ही डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने भी 3 दिसंबर 2019 को संपत्ति के हस्तांतरण आदि पर रोक लगा दी थी। रिलायंस कैपिटल ने कहा, इन वजहों से कंपनी अपनी परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण नहीं कर पा रही है, लिहाजा कर्ज व ब्याज भुगतान में देर हो रही है।

एचडीएफसी ने 523.9 करोड़ रुपये और ऐक्सिस बैंक ने 100.6 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है

एचडीएफसी ने 523.9 करोड़ रुपये और ऐक्सिस बैंक ने 100.6 करोड़ रुपये का कर्ज दिया है। बैंकों व वित्तीय संस्थानों की कुल बकाया रकम 31 जनवरी 2020 को 641.7 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बीएसई को भेजी सूचना में ये बातें कही।

अल्पावधि व लंबी अवधि के कर्ज समेत कुल वित्तीय देनदारी 18,921 करोड़ रुपये है और इसमें 31 जनवरी 2020 तक का ब्याज शामिल है।

इस बीच, रिलायंस होम फाइनैंस ने एक्सचेंज को सूचित किया है कि उसने सावधि कर्ज व कैश क्रेडिट पर ब्याज भुगतान में चूक की है।

कंपनी के पास लिक्विड म्युचुअल फंड में करीब 700 करोड़ रुपये का निवेश है। हालांकि 20 नवंबर 2019 के अदालत के आदेश के बाद कंपनी के संपत्ति भुगतान पर रोक लगी हुई है।

रिलायंस होम फाइनैंस ने कहा कि कंपनी के लेनदारों ने इंटर क्रेडिटर करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 7 जून 2019 के परिपत्र के मुताबिक कर्ज समाधान योजना पर पहुंचने के लिए है।

कुल बकाया उधारी 3,890 करोड़ रुपये है। अल्पावधि व लंबी अवधि के कर्ज समेत सूचीबद्ध इकाइयों पर कुल वित्तीय देनदारी 11,955 करोड़ रुपये थी।

क्यूआईपी से 1,700 करोड़ रुपये जुटाएगी पीएनबी हाउसिंग

अभिजित लेले
मुंबई, 3 मार्च

पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस की योजना मार्च 2023 तक पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) के जरिये 1,700 करोड़ रुपये तक जुटाने की है। यह रकम कारोबारी बढ़त के लिए जुटाई जा रही है। कंपनी के निदेशक मंडल ने क्यूआईपी के जरिए रकम जुटाने की योजना को मंजूरी दे दी। निदेशक मंडल की बैठक के बाद कंपनी ने बीएसई को यह जानकारी दी। कंपनी का शेयर बीएसई पर एक फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 341.7 रुपये पर बंद हुआ।

बोर्ड ने कंपनी को सलाह दी है कि क्यूआईपी बंद होने के बाद वह क्वॉलिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग की पेशकश करे और उस आधार पर इक्विटी शेयर या प्रतिभूतियों का तरजीही आवंटन करे।

हाउसिंग फाइनैंस कंपनी ने क्यूआईपी की पेशकश की समयसारणी के बारे में नहीं बताया। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक, कंपनी ने पहले अपना कर्ज घटाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी जुटाने की योजना बनाई थी। लेकिन बाद में उसे घटाकर 1,500-1,600 करोड़ रुपये करना पड़ा ताकि प्रवर्तक के तौर पर पीएनबी के पास 26 फीसदी हिस्सेदारी बनी रहे।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान करीब 3,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी जुटाई थी। कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात दिसंबर 2019 में बढ़कर 17.06 फीसदी हो गया, जो 31 मार्च 2019 को 13.98 फीसदी रहा था।

2023 में आईपीओ लाएगी बिगबास्केट

विभु रंजन मिश्रा
बेंगलूरु, 3 मार्च

ऑनलाइन फर्म बिगबास्केट का इरादा साल 2023 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने का है और कंपनी को लग रहा है कि तब तक उसका एबिटा सकारात्मक हो जाएगा।

ब्याज, कर और ह्रास आदि से पहले की आय यानी एबिटा अहम मानक है क्योंकि यह कारोबार की सेहत बताता है और यह भी कि क्या वह परिचालन खर्च को पूरा करने के बाद नकदी सृजित करने में सक्षम है। कंपनी के सहसंस्थापक और सीईओ हरि मेनन ने कहा, लक्ष्य हासिल करने के लिए बिगबास्केट को एक बार फिर रकम जुटाने की दरकार होगी, जो आखिरी होगा। मेनन ने कहा कि जुलाई तक बिगबास्केट मार्जिन में योगदान को लेकर सकारात्मक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि वह हर तरह की लागत (कॉरपोरेट लागत को छोड़कर) के प्रबंधन में सक्षम होगी। मेनन ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, हमारा इरादा एबिटा को लेकर सकारात्मक बनने का है और वित्त वर्ष 22 व वित्त वर्ष 23 के बीच हम इसे हासिल कर लेंगे।

कंपनी कई शहरों में मार्जिन में योगदान को लेकर सकारात्मक हो गई है जहां वह मौजूद है। मुख्य किराना कारोबार नकदी सृजित करना शुरू कर चुका है, ऐसे में बाहरी फंडों पर उसकी निर्भरता घटी है। मेनन ने कहा कि जुलाई-अगस्त तक बिगबास्केट एक बार फिर रकम जुटाएगी।

बिगबास्केट का इरादा साल 2023 में आईपीओ लाने और वित्त वर्ष 2021 में राजस्व 7,000 करोड़ रुपये के पार ले जाने का है। हालांकि उन्होंने आंकड़ों का खुलासा करने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह 15-20 करोड़ डॉलर के दायरे में हो सकता है।

मेनन ने कहा, उम्मीद है कि रकम जुटाने के लिहाज से जुलाई-अगस्त का दौर आखिरी होगा और हम उसके बाद गंभीरता से आईपीओ पर विचार कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगले तीन साल में हम आईपीओ के लिए तैयार हो जाएंगे।

बिगबास्केट को मौजूदा वित्त वर्ष 5,000 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ समाप्त होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022 में उसे एक अरब डॉलर के आंकड़ों के साथ राजस्व 7,000 करोड़ रुपये के पार जाने की संभावना दिख रही है।

लाभ हासिल करने के लिए बिगबास्केट ने नए शहरों में विस्तार नहीं करने का फैसला लिया है और उसके बजाय वह मौजूदा बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। अलीबाबा के समर्थन वाली यह कंपनी 24 शहरों में मौजूद है और 10 अग्रणी शहर उसके राजस्व में करीब 85 फीसदी का योगदान करते हैं।

मेनन ने कहा, विस्तार के लिहाज से हम काफी कुछ कर चुके हैं। इसकी वजह यह है कि किराना काफी विशाल बाजार है और इसमें गहराई से उतरने का विचार है।

बिगबास्केट अपने लखनऊ आधार से कानपुर जैसे शहर, चंडीगढ़ से लुधियाना, बड़ोदरा से आणंद और विजयवाड़ा से गुंटूर को सेवाएं दे रही है। मेनन ने कहा, हम सिर्फ ऐसा ही विस्तार करेंगे, जो सीमा के विस्तार जैसा ही है। अगले कुछ महीने में कंपनी की योजना इलाहाबाद और फरीदाबाद जैसे अन्य शहरों को अपने नेटवर्क में जोड़ने की है।

एसबीआई काड्र्स आईपीओ में एनबीएफसी की उधारी योजना पर असर

अमीर निवेशकों से मांग की उम्मीद में एनबीएफसी ने काफी रकम उधार ली थी पर लगता है कि वह गलत दिशा में फंस गई

समी मोडक
मुंबई, 3 मार्च

आरंभिक सार्वजनिक निर्गम में धनाढ्य निवेशकों (एचएनआई) को कर्ज देकर दांव लाने में मदद करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की योजना पर कोरोनावायरस के चलते पैदा हुए जोखिम का असर पड़ा है।

धनाढ्य निवेशकों से भारी मांग का अनुमान लगाते हुए इन फर्मों ने काफी रकम उधार ली थी। हालांकि अब उन्हें डर है कि अब यह रकम बिना इस्तेमाल के पड़ा रह सकता है। आईपीओ के लिए उधार देने की खातिर एनबीएफसी मोटे तौर पर वाणिज्यिक पत्रों के जरिए रकम जुटाती है। वह 3 से 5 फीसदी की दर पर एचएनआई को उधार देती हैं। मांग का अनुमान लगाते हुए रकम जुटाई गई थी, जो पिछले हफ्ते तक एसबीआई काड्र्स के मामले में मजबूत था क्योंकि ग्रे मार्केट में प्रीमियम 50 फीसदी तक था।

हालांकि बाजार में बिकवाली के बाद यह प्रीमियम आधे से कम रह गया है, जब बेंचमार्क सूचकांकों में सात दिनों में 8 फीसदी की गिरावट दिखी थी। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि एनबीएफसी और एचएनआई मांग परिदृश्य में हुए बदलाव के आधार पर अपनी योजना दुरुस्त कर रहे हैं।

एनबीएफसी के एक अधिकारी ने कहा, एचएनआई श्रेणी में आवेदन का स्तर शुरुआती अनुमान के मुताबिक नहीं होगा। उधार देने को प्रतिबद्ध एनबीएफसी अब गलत दिशा में फंस गई हैं। एचएनआई की उधारी आईपीओ की अनुमानित मांग व संभावित सूचीबद्धता कीमत पर आधारित है। अगर सूचीबद्धता कीमत ज्यादा होती तो एचएनआई अपने मनमुताबिक आवंटन के लिए ज्यादा उधार लेते। अगर सूचीबद्धता पर फायदा का अनुमान कम होता है तो वे बड़ा दांव लगाने से परहेज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आईआरसीटीसी के एचएनआई श्रेणी में 350 गुना आवेदन मिले थे। एनबीएफसी ने करीब 35,000 करोड़ रुपये उधार देकर मोटा माल कमाया। एचएनआई ने भी सूचीबद्धता पर काफी कमाई की क्योंकि यह दोगुने से ज्यादा पर सूचीबद्ध हुआ।

एक निवेश बैंकर ने कहा, कुछ एनबीएफसी एसबीआई काड्र्स में आईआरसीटीसी जैसी मांग की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि आवेदन काफी कम होंगे, ऐसे में आईपीओ के लिए उधारी की मांग पर चोट पहुंचेगी।

एसबीआई काड्र्स के आईपीओ को मंगलवार को 87 फीसदी आवेदन मिले और ज्यादातर मांग छोटे निवेशकों की तरफ से देखने को मिली। क्यूआईबी श्रेणी में 21 फीसदी आवेदन मिले और एचएनआई श्रेणी में 47 फीसदी। क्यूआईबी बुक बुधवार को बंद हो जाएगा, वहीं अन्य श्रेणी के लिए गुरुवार तक का समय है। बाजार के प्रतिभागियों ने कहा कि एचएनआई अब क्यूआईबी से संकेत लेंगे। अगर क्यूआईबी श्रेणी ठीक रहती है तो वे कुछ दांव लगा सकते हैं।

एसबीआई काड्र्स आईपीओ पर ग्रे मार्केट में प्रीमियम आधे से ज्यादा घट गया है

एसबीआई आईपीओ: अमीर निवेशकों के लिए बढ़िया दांव

यदि आरंभिक सार्वजनिक निर्गम को कई गुना अभिदान मिला तो सूचीबद्धता पर बढ़त सीमित हो सकती है

संजय कुमार सिंह
नई दिल्ली, 3 मार्च

जब एसबीआई काड्र्स जैसे आईपीओ आते हैं तो इनमें सूचीबद्धता के दिन अच्छी तेजी की उम्मीद रहती है। अमीर निवेशक (एचएनआई) ऐसे आईपीओ में दांव लगाने के लिए अक्सर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से उधार लेते हैं। हालांकि ऐसे दांव में जोखिम भी अधिक होता है, जिन पर एचएनआई को ध्यान रखे जाने की जरूरत होगी।

यदि किसी व्यक्ति का आवेदन 2 लाख रुपये से अधिक के लिए है, तो वह एचएनआई श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस श्रेणी में आवंटन इस तरह से होता है: यदि एचएनआई हिस्से को 'एक्स' गुना अभिदान मिलता है तो प्रत्येक एचएनआई को उसके द्वारा किए गए आवेदन का 1/एक्स हिस्सा आवंटित किया जाता है। एचएनआई अक्सर ज्यादा शेयर पाने के लिए अक्सर पैसा उधार लेते हैं। शेयरखान बीएनपी पारिबा फाइनैंशियल सर्विसेज के मुख्य कार्याधिकारी शंकर वैलाया कहते हैं, 'मान लीजिए कि कोई एचएनआई 1 करोड़ रुपये के शेयर खरीदना चाहता है। यदि कुल अभिदान 10 गुना है और वह सिर्फ अपने पास जमा पूंजी का इस्तेमाल करता है तो उसे महज 10 लाख रुपये के शेयर आवंटित किए जा सकते हैं।' अमीर निवेशकों को आवेदन करने से पहले सूचीबद्धता लाभ को ध्यान में रखना चाहिए। वैलाया कहते हैं, 'सूचीबद्धता के दिन आने वाली तेजी पर्याप्त हो सकती है जिससे आवेदक ब्याज खर्च चुकाने के बाद भी मुनाफा कमाने में सक्षम हो सकता है।'

ऐसे ऋण लेने में दो प्रमुख जोखिम जुड़े होते हैं। सूचीबद्धता के दिन लाभ के बजाय नुकसान भी हो सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनी के मामले में भी, कभी कभार बाजार धारणा आवेदन के समय और सूचीबद्धता के समय के बीच बदल सकती है। ज्यादा विषम कारकों (जैसे कि कोरोनावायरस महामारी) से धारणा प्रभावित हो सकती है।

अन्य जोखिम है एचएनआई को मिलने वाले आवंटन की मात्रा। सेबी के साथ पंजीकृत निवेश सलाहकार पर्सनलफाइनैंसप्लान डॉटइन के संस्थापक दीपेश राघव कहते हैं, 'यदि आईपीओ को मिलने वाले अभिदान का स्तर अनुमान से ज्यादा रहता है तो एचएनआई को कम आवंटन मिलेगा। लेकिन फिर भी उसे उधार ली गई पूरी रकम पर ब्याज चुकाना होगा, जिससे उसे नुकसान हो सकता है।' वह कहते हैं कि आवंटन का स्तर कम रहने से सूचीबद्धता पर लाभ निवेशक के लिए ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। पहले ही यह अनुमान लगाना आसान नहीं होता है कि आईपीओ को कितना अभिदान मिलेगा, क्योंकि अमीर निवेशक मुख्य तौर पर आखिरी दिन आवेदन करते हैं।

इन ऋणों पर ब्याज दर से भी निवेशक के मुनाफे पर बोझ पड़ता है। एनबीएफसी म्युचुअल फंडों से पैसा जुटाती हैं। किसी ज्यादा लोकप्रिय आईपीओ के मामले में, म्युचुअल फंड सिर्फ ऊंची दर पर उधार देना पसंद करते हैं।

एचएनआई के लिए सबसे अनुकूल परिदृश्य तब होता है जब सूचीबद्धता का लाभ अच्छा हो, लेकिन अभिदान का स्तर बहुत ज्यादा नहीं हो। हालांकि ऐसा हो सकता है, ये आंतरिक तौर पर परस्पर विरोधी परिणाम होते हैं। यदि आईपीओ लोकप्रिय है तो सूचीबद्धता के दिन अच्छी तेजी की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन ऐसे आईपीओ के लिए ज्यादा संख्या में आवेदन भी किए जा सकते हैं। इससे सूचीबद्धता का लाभ और आवंटन मिलना आसान नहीं रहता। ज्यादा कर्ज से जुड़े किसी निवेश में जोखिम भी अधिक होता है।

बैंकबाजार डॉटकॉम के मुख्य कार्याधिकारी अधिल शेट्टी कहते हैं, 'आईपीओ फंडिंग के जरिये आईपीओ में पैसा लगाना ज्यादा जोखिम वाला निवेश है। यदि हालात प्रतिकूल रहते हैं तो इसमें ज्यादा नुकसान हो सकता है।'

अमीर निवेशकों के लिए फायदा-नुकसान

निवेशक द्वारा निवेशिक रकम (2ज)	500,000
उधार ली गई रकम	2,45,00,000
आईपीओ में निवेशित कुल रकम	2,50,00,000
ज्यादा अभिदान मिलने की संख्या	50
वित्त की ब्याज दर	11%
निवेशक को मिले शेयरों का मूल्य	500,000
गैर-इस्तेमाल ऋण	2,45,00,000
लिए गए ऋण पर ब्याज	51,685
पहले दिन 15 प्रतिशत की तेजी पर लाभ	75,000
एसटीसीजी 15 प्रतिशत	11,250
ब्याज भुगतान के बाद लाभ	12,065
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	126%
पहले दिन 15 प्रतिशत गिरावट पर नुकसान	-75,000
ब्याज भुगतान के बाद नुकसान	-126,685
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	-1321%

आईईएक्स शुरू करेगा गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने अभी गैस कारोबार के नियम नहीं किए हैं जारी

श्रेया जय और शाइन जैकब
नई दिल्ली, 3 मार्च

भारत के प्रमुख पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) ने अपने प्राकृतिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'इंडियन गैस एक्सचेंज' (आईजीएक्स) के लिए सदस्यों और गैस खरीदारों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) को देश में गैस कारोबार के लिए दिशा-निर्देश जारी करने बाकी हैं।

आईजीएक्स दहेज, हजीरा और काकीनाडा में स्पॉट एवं वायदा अनुबंध की पेशकश करेगा। जहां पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड (पीएलएल) दहेज में एलएनजी टर्मिनल का परिचालन करती है, वहीं शेल हजीरा में अन्य टर्मिनल का परिचालन करती है। काकीनाडा कृष्णा गोदावरी बेसिन से तैयार प्राकृतिक गैस के लिए लैंडफॉल पॉइंट है।

आईजीएक्स बाजार से एक दिन पहले स्पॉट अनुबंध की पेशकश करेगा जिसका मतलब है कि गैस पारंपरिक रूप से अगले दिन डिलिवर होगी। वायदा अनुबंध दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और पाक्षिक बाजारों के लिए है।

मौजूदा समय में, एलएनजी आपूर्ति अनुबंधों और मूल्य निर्धारण, दोनों के संदर्भ में विनियमित नहीं है, जबकि घरेलू गैस कीमतें सरकार द्वारा तय की जाती हैं। सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा तैयार गैस के लिए आपूर्ति अनुबंध सरकारी मानकों से जुड़े हुए हैं।

विद्युत कारोबार में 90 प्रतिशत की भागीदारी वाला आईईएक्स अगले पांच साल में आईजीएक्स के लिए 10 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की योजना बना रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि गैस बाजार की वृद्धि क्षमता को ध्यान में रखकर यह योजना तैयार की गई। एक कंपनी के अधिकारी ने कहा, 'भारत में गैस बाजार 2.5 गुना की वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। वर्ष 2030 तक यह बाजार 166 से बढ़कर 380 एमएमएससीएमडी पर पहुंच जाने का अनुमान है। अनुकूल नीतियों की मदद से भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का योगदान दोगुना बढ़कर 15 प्रतिशत हो सकता है।' हालांकि मौजूदा सरकार पिछले तीन साल से गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज को लेकर उत्साहित रही है, लेकिन अभी इस बारे में नियम बनाए जाने बाकी हैं।

आईईएक्स की योजनाओं पर पीएनजीआरबी को निर्णय लेना है। पीएनजीआरबी के एक अधिकारी ने संकेत दिया कि वे गैस हब तैयार किए जाने की प्रक्रिया से लंबे समय से जुड़े हुए थे और अभी गैस कारोबार के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाने हैं। गेल और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा नियोजित गैस एक्सचेंज में हिस्सेदारी लिए जाने की संभावना थी, जिससे प्राकृतिक गैस कारोबार हब के निर्माण में मदद मिलती। अप्रैल 2018 में, केपीएमजी ने भारत में गैस हब निर्माण के लिए पीएनजीआरबी को रिपोर्ट सौंपी थी।

गेल के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी अब तक आईईएक्स की योजना के खिलाफ नहीं रही है। गेल के एक अधिकारी ने कहा, 'यह स्वतंत्र दुनिया है। लेकिन आपको ऐसी संस्था की कानूनी वैधता देखनी होगी, क्योंकि पीएनजीआरबी द्वारा निर्धारित नियम अभी अधिसूचित नहीं हैं।' सरकार को इस बारे में निर्णय लेने की जरूरत होगी कि क्या नामांकन आधार पर आवंटित घरेलू क्षेत्रों से उत्पादित गैस का कारोबार होगा।

संभावित सदस्यों के लिए प्रजेंटेशन में आईजीएक्स ने कहा है कि एक्सचेंज से टर्मिनलों और पाइपलाइनों की बिक्री और इन्फ्रास्ट्रक्चर उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस प्रजेंटेशन में कहा गया, 'छोटे उद्योग भी प्रतिस्पर्धी कीमत पर गैस खरीदने के लिए इस एक्सचेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के कायाकल्प में बड़ी मदद मिलेगी।' आईजीएक्स अपने प्लेटफॉर्म पर खरीदारों के तौर पर उर्वरक उद्योग और सिटी गैस वितरकों को आकर्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित दे रहा है।

गैस कारोबार की दिशा में पहल

- इंडियन गैस एक्सचेंज के लिए सदस्यों और गैस खरीदारों की तलाश शुरू
- आईजीएक्स दहेज, हजीरा एवं काकीनाडा में स्पॉट एवं वायदा अनुबंधों की पेशकश करेगा
- आईईएक्स अगले पांच साल में आईजीएक्स के लिए 10 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश की योजना बना रहा है

नई तकनीक से बढ़ेगी रेल पटरियों की उम्र

अदिति दिवेकर और शाइन जैकब
मुंबई, 3 मार्च

रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा के मोर्चे पर अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए हाल में जस्ते की परत चढ़ी पटरियां इस्तेमाल करने को मंजूरी दी है। इन पटरियों का इस्तेमाल विशेष रूप से देश के उन तटीय क्षेत्रों में होगा, जहां पटरियों के जल्द जंग लग जाती है। रेलवे बोर्ड भारतीय रेल की शीर्ष संस्था है।

सूत्रों के मुताबिक भारतीय रेल को हर साल करीब 1,000 ट्रैक किलोमीटर या 120,000 टन जस्ते की पटरियों की जरूरत होगी। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि पटरियों की आदर्श उम्र करीब 12 साल है, लेकिन जंग की वजह से पटरियों को हर दो साल बाद बदलना पड़ता है। रेलवे की अनुसंधान इकाई डिजाइन ऐंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (आरडीएसओ) ने जस्ता एल्युमीनियम धातु परत के मानकों को लेकर निर्देश जारी किए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि ये मानक अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ और उद्योग के अन्य भागीदारों के साथ मिलकर तैयार किए हैं।

इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाने के लिए जस्ते का इस्तेमाल किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ के निदेशक राहुल शर्मा ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'रेलवे को जंग की वजह से हर साल मोटा नुकसान होता है। इसके अलावा जंग से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा होता है। इसका दैनिक यात्रा पर भी असर पड़ता है क्योंकि ट्रेन की रफ्तार कम हो जाती है, जिससे कुशलता भी प्रभावित होती है।'

भारतीय रेल की वित्त वर्ष 2019 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इसके नतीजतन 2018-19 में 59 ट्रेन दुर्घटनाएं हुईं, जिनकी संख्या 2017-18 में 72 थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि एक लाख ट्रेन किलोमीटर पर होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को सुरक्षा का एक अहम सूचकांक माना जाता है। यह 2018-19 में घटकर 0.05 पर आ गया, जो 2017-18 में 0.06 पर था। वैश्विक स्तर पर लंदन ट्यूब और फ्रेंच रेलवे नेटवर्क पहले ही पटरियों में जंग लगने वाले क्षेत्रों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैश्विक उदाहरणों का अनुसरण करते हुए भारतीय रेल भी नई तकनीक को अपनाने पर ध्यान दे रही है।

पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण की रफ्तार तेज हुई है। वर्ष 2018-19 में 4,181 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण किया गया। वहीं जनवरी 2020 तक 3,872 किलोमीर रेल ट्रैक बिछाया गया है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 का लक्ष्य 3,900 किलोमीटर है। भारतीय रेल केवल सेल से पटरियां खरीदती थी, लेकिन अब यह सरकारी कंपनी और नवीन जिंदल की अगुआई वाली जिंदल स्टील ऐंड पावर पटरियों की आपूर्ति करती हैं।

शर्मा ने कहा, 'रेलवे ने सेल को जस्ते की परत चढ़ी 2,000 टन पटरियों का ऑर्डर दिया है। उन्होंने साबरमती (अहमदाबाद के नजदीक) में अपनी वर्कशॉप में भी इस तकनीक को अपनाने की योजना बनाई है, जो बुलेट ट्रेन मरम्मत यार्ड के लिए हब होगा।'

जस्ता बनेगा मददगार

- रेलवे का सेल को जस्ते की परत चढ़ी 2,000 टन पटरियों का ऑर्डर
- पटरियां आदर्श स्थिति में 12 साल चलती हैं, लेकिन जंग लगने से चल पाती हैं केवल दो साल
- अंतरराष्ट्रीय जस्ता संघ मुफ्त में नई तकनीक की कर रहा आपूर्ति
- रेल पटरियों में जंग से यात्रियों की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था सीएए पर शीर्ष अदालत पहुंची

अर्चिस मोहन
नई दिल्ली, 3 मार्च

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को याचिका दायर की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत का आंतरिक मामला है और 'किसी भी विदेशी पक्ष' को देश की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन की उच्चायुक्त मिशेल बेश्लेट ने जिनेवा स्थित भारत के स्थायी मिशन को सोमवार शाम सूचित किया कि उनके कार्यालय ने सीएए पर उच्चतम न्यायालय में हस्तक्षेप की अर्जी दाखिल की है। उच्चतम न्यायालय इस नए कानून को चुनौती देने वाली बहुत सी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार सुबह भाजपा सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विकास के लिए शांति, सौहार्द और एकता अत्यंत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि देश को अस्थिर करने के लिए बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं।

मोदी ने कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को 'भारत माता की जय' जैसे नारे में भी साजिश की बू आती है और इसे संदेह की नजर से देखते हैं। हाल में एक कार्यक्रम में सिंह ने कहा था कि 'भारत माता की जय' के नारे का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इस नारे का इस्तेमाल कर भारत के बारे में भावनात्मक एवं उग्र राष्ट्रवाद का विचार पैदा किया जा रहा है।

लोकसभा में मंगलवार को बैंकिंग नियमन (संशोधन) विधेयक पेश किया गया। हालांकि दिल्ली में हिंसा के मुद्दे की वजह से संसद में कामकाज नहीं हो सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि सरकार दिल्ली हिंसा पर चर्चा को तैयार है।

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री से मिले और हिंसा के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शने का आग्रह किया, भले ही वह किसी भी दल से जुड़ा हो। यह मुलाकात संसद में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई, जो करीब आधे घंटे चली। इस मुलाकात के बाद केजरीवाल ने हालात को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रशंसा की।

मुनाफाखोरी की आधी रकम जमा कराएं

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 3 मार्च

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रियल एस्टेट की दो कंपनियों को अलग अलग किस्तों में तथाकथित मुनाफाखोरी की 50 फीसदी रकम जमा कराने के लिए कहा है और अंतिम फैसला आने तक राष्ट्रीय मुनाफाखोरीरोधी प्राधिकरण (एनएए) के आदेश पर स्थगन लगा दिया।

अपने एक आदेश में न्यायालय ने कहा, 'याचिकाकर्ता को मुनाफाखोरी की रकम का 50 फीसदी जमा करने का निर्देश दिया जाता है। यह रकम दो बराबर बराबर मासिक किस्तों में जमा कराया जाएगा।'

न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जमा कराई जाने वाली रकम को ब्याज वाली सावधि जमा प्राप्तियों में रखा जाए। ये मामले नोएडा और गुरुग्राम स्थित परियोजनाओं से संबंधित दो बिल्डरों के हैं। एनएए ने इन दोनों बिल्डरों पर जीएसटी का फायदा घर खरीदारों को नहीं देने पर प्रत्येक पर 5-5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

इन परियोजनाओं की शुरुआत जीएसटी शुरू होने से पहले हो गई थी लेकिन ये जुलाई 2017 के बाद तक जारी रहीं और तब तक जीएसटी लागू हो चुका था। एनएए ने मुनाफाखोरी की रकम की गणना जीएसटी प्रणाली में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट और कंपनियों के सकल कारोबार के आधार पर किया।

याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक रस्तोगी ने कहा, 'किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के लिए शुरुआती दौर में जमीन लागत के मद में भारी भरकम निवेश की जरूरत होती है और ऐसे में कुल कारोबार में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुपात होने से असंगत और अनुचित परिणाम सामने आ सकते हैं।' एनएए के नियमों में मुनाफाखारी की रकम की गणना के लिए कोई विशेष तरीका नहीं है और इसे मामले दर मामले के आधार पर निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दिया गया है। खेतान ऐंड कंपनी में पार्टनर रस्तोगी ने कहा कि मुनाफाखोरी की राशि के निर्धारण के लिए किसी स्पष्ट तरीके के अभाव में इस मामले से जुड़े समस्त कारकों के विस्तृत विश्लेषण की जरूरत है।

एचएनआई का वाणिज्यिक प्रॉपर्टी में निवेश पर जोर

राघवेंद्र कामत
मुंबई, 3 मार्च

पिछले साल दिल्ली स्थित एक धनाढ्य निवेशक (एचएनआई) ने मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित रहेजा टाइटेनियम परिसर में 29,495 वर्गफुट वाणिज्यिक संपत्ति खरीदी थी। यह विक्रेता केन्या का था। इसी तरह से एक तकनीक आधारित फंड ने नवी मुंबई स्थित एलऐंडटी सीवुड्स और बांद्रा कुर्ला परिसर स्थित द कैपिटल में क्रमश: 48,000 वर्गफुट और 7,721 वर्गफुट जगह खरीदी थी।

ये दो उदाहरण महज अपवाद नहीं हैं। सलाहकारों और निवेशकों का कहना है कि ऐसे समय जब आवासीय बाजार मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसमें निवेशकों को कम प्रतिफल मिल रहा है, तब बड़े शहरों की कार्यालय परिसंपत्तियों की खुदरा बिक्री में तेज उछाल नजर आ रही है।

देश के शीर्ष सात शहरों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के प्रथम श्रेणी के कार्यालय स्थल निर्माणाधीन हैं और अगले कुछ वर्षों में ये पूरे हो जाएंगे। एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 25 फीसदी (63,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति) बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। मुंबई स्थित फंड प्रबंधक नीसस फाइनैंस के मुताबिक पिछले वर्ष देश के शीर्ष पांच शहरों में व्यावसायिक इमारतों की खुदरा बिक्री 6,000 करोड़ रुपये मूल्य की रही थी। भारत की सबसे बड़ी रियल एस्टेट सेवा कंपनी जेएलएल के मुख्य कार्याधिकारी और कंट्री हेड रमेश नायर ने कहा, 'देश में करीब 1,80,000 अत्यधिक धनाढ्य निवेशक हैं जो 10 फीसदी सालाना की दर से बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आवासीय बाजार का कारोबार धीमा हुआ है ऐसे में एचएनआई बहुत सक्रियता से अन्य परिसंपत्ति वर्गों की तरफ देख रहे हैं।'

पिछले साल देश के सबसे बड़े पांच शहरों में 6,000 करोड़ रुपये की व्यावसायिक प्रॉपर्टी की खुदरा बिक्री हुई

नायर ने कहा कि एक ओर जहां आवासीय परिसंपत्तियों से 2-2.5 फीसदी का प्रतिफल मिल रहा है पूंजी में सालाना 1 से 2 फीसदी की वृद्धि हो रही है वहीं वाणिज्यिक परिसंपत्तियों से 7 से 9 फीसदी का किराया प्रतिफल मिल रहा है और इसमें पूंजीगत वृद्धि सालाना 4 से 8 फीसदी की है। उन्होंने कहा कि जेएलएल ने पिछले वर्ष शीर्ष सात शहरों में ऐसे कई सौदे किए।

इतना ही नहीं, परिसंपत्ति कंपनियां और कंसल्टेंट्स बढ़ चढ़ कर खुदरा बिक्री के कारोबार में उतर रहे हैं। 2019 के आरंभ में रियल्टी की दिग्गज कंपनी प्रेस्टीज एस्टेट्स ने अपने कार्यालय परिसंपत्तियों के 25 फीसदी की बिक्री व्यक्तिगत निवेशकों को खुदरा बिक्री के तौर पर करने की घोषणा की थी। कंपनी ने यह योजना उच्च प्रतिफल वाले रियल्टी परिसंपत्तियों के लिए बनाई थी।

वाणिज्यिक परिसंपत्तियों की खुदरा बिक्री पर ध्यान देने के लिए हाल में स्थापित किए गए एनारॉक कॉमर्शियल के मुख्य कारोबार अधिकारी बप्पादित्य बसु ने कहा, 'कार्यालय परिसंपत्तियों के कारोबार में शामिल कंपनियों में से कुछ कंपनियों को छोड़कर ज्यादातर कंपनियां स्ट्रेटा बिक्री करने को इच्छुक हैं।'

बसु ने कहा, 'दक्षिणी भारत के उलट इधर ज्यादातर डेवलपर निर्माण ऋण लेते हैं और रकम का भुगतान के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऋण चुकता करने में 8 से 9 वर्ष का समय लगता है लेकिन स्ट्रेटा बिक्री के जरिये वे निर्माण देयताओं के 25 फीसदी का बंदोबस्त कर सकते हैं और इस तरह से परियोजना से बाहर निकलने की अवधि को घटा सकते हैं।'

ठोस सबूतों बिना स्वतंत्र निदेशकों पर कार्रवाई नहीं

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने बिना सबूतों के स्वतंत्र निदेशकों और गैर-प्रवर्तकों के खिलाफ अभियोजन को हतोत्साहित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय की तरफ से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि स्वतंत्र या गैर-कार्यकारी निदेशकों की जिम्मेदारी उन कार्यों तक ही सीमित होगी, जो उनके संज्ञान में होंगे, बोर्ड की प्रक्रिया से जुड़े होंगे और जिनमें उनकी सहमति होगी। मंत्रालय ने सभी पंजीयकों को मानक प्रक्रिया का पालन करने को कहा है। *बीएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 15

प्रताड़ना का लाइसेंस!

केंद्र सरकार बजट में घोषित 'विवाद से विश्वास' योजना के माध्यम से राजस्व में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यह योजना लोगों का वह समय और पैसा बचाने में मदद करेगी जो ऐसे मामलों में जाया होता है। दरअसल करीब 9.3 लाख करोड़ रुपये के 4 लाख से अधिक प्रत्यक्ष कर संबंधी मामले विभिन्न स्तरों पर अपील में लंबित हैं। योजना के अनुसार यदि कोई करदाता चालू वित्त वर्ष के अंत तक कर चुकाने को तैयार हो जाता है तो उसे ब्याज, जुर्माने और अभियोग से बचाव मिलेगा। करदाताओं के पास यह विकल्प होगा कि वे 31 मार्च के बाद और 30 जून के पहले विवाद निपटा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ऐसे वक्त पर विवादों को कम करने और संसाधन बढ़ाने का प्रयास कर रही है जब लग रहा है कि वह राजस्व लक्ष्य से काफी पीछे रह सकती है।

परंतु योजना को लागू करने का तरीका चिंता की वजह बन सकता है। इस समाचार पत्र में प्रकाशित खबरों के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अधिकारियों की सालाना वेतन वृद्धि को योजना के तहत किए जाने वाले संग्रह से जोड़ने का निर्णय लिया है। सीबीडीटी कार्यालय के एक ज्ञापन के मुताबिक संग्रह के नतीजे भविष्य में इन अधिकारियों की तैनाती में भी अहम भूमिका निभाएंगे। यह विवाद निस्तारण योजना घोषित होने के तत्काल बाद विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वे शनिवार को और छुट्टी के दिन भी काम करें ताकि जब योजना की आधिकारिक शुरुआत की जाए तो वे तत्काल संग्रह शुरू कर सकें। यह करदाताओं के शोषण का हथियार है। ऐसे में सरकार की इस मुद्दे से निपटने की शुरुआत ही गलत है। यह समझना आवश्यक है कि इतने ज्यादा कर विवाद क्यों हैं? पहले तो सरकार राजस्व संग्रह के अतिमहत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय करती है और कर विभाग पर यह दबाव बनाती है कि वे ऐसी कर मांग करें जिसका करदाता प्रतिरोध करते हैं। इससे विवाद उत्पन्न होते हैं। अब प्रदर्शन के आकलन का नया लक्ष्य कर अधिकारियों को मजबूर करेगा कि वे करदाताओं से विवादित राशि वसूल करने का हरसंभव प्रयास करें। यह स्वाभाविक रूप से शोषण की ओर ले जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि करदाता लोगों को बार-बार फोन कर रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह कि योजना की मामूली सफलता भी सरकार को ऐसी मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे विवाद बढ़ेंगे और फिर निस्तारण की पेशकश की जाएगी। इससे लागत बढ़ेगी और कारोबारी सुगमता प्रभावित होगी। यह सरकार के कर आतंक खत्म करने के घोषित लक्ष्य के खिलाफ जाएगा।

निश्चित तौर पर विवाद की समस्या को जड़ के जरिये ही हल किया जा सकता है। सरकार को जिम्मेदार ढंग से बजट तैयार करना होगा। वह अपने ताजा राजस्व स्तर के साथ लगातार मौजूदा ढंग से व्यय नहीं कर सकती। अति आशावादी राजस्व अनुमान न केवल करदाताओं की प्रताड़ना की वजह बनते हैं बल्कि सरकार के व्यय में भी अनिश्चितता आती है। सरकारी विभाग भी सुनिश्चित नहीं हैं कि उन्हें वित्त वर्ष के आरंभ में आवंटित राशि व्यय करने के लिए मिलेगी या नहीं।

सरकार को कर विवादों के तेज निस्तारण की दिशा में काम करना होगा। संभव है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था में जहां कर कानून जटिल हैं, वहां विवाद भी होंगे। ऐसे में ऐसी व्यवस्था लागू करनी होगी ताकि इन विवादों को समय पर निपटाया जा सके। भारत को निजी निवेश के लिए इसलिए भी कठिन माना जाता है क्योंकि कर विभाग और करदाताओं के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ताजा कदम से समस्या बढ़ेगी।

अजय मोहंती

देश में ऊर्जा सुरक्षा का बदलता परिदृश्य

ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो या तो पुरानी चिंताओं में नई जटिलताएं आई हैं या फिर ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बदलाव से जुड़ी नई चिंताएं उभर रही हैं। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **अरुणाभ घोष**

देश की अर्थव्यवस्था का आकार 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता है। देश में ऊर्जा सुरक्षा का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। देश में ऊर्जा सुरक्षा अहम संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन संसाधनों की कीमत भी कम और अनुमान के अनुरूप होनी चाहिए ताकि आपूर्ति क्षेत्र में कोई बाधा न हो। ऐसा इसलिए ताकि पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायित्व सुनिश्चित किया जाए। इसके आयामों की बात करें तो या तो पुरानी चिंताओं से संबंधित नई जटिलताएं सामने आ रही हैं या फिर ऊर्जा बदलाव के क्षेत्र में नई चिंताएं उभर रही हैं।

पहली बात, आपूर्ति की सुरक्षा ऊर्जा के स्थानांतरण, भूराजनीति आदि से प्रभावित होती है। भारत अपनी आवश्यकता के तेल का 84 फीसदी आयात करता है। सन 2022 तक तेल आयात पर निर्भरता घटाकर 67 फीसदी करने के लक्ष्य के बावजूद इसमें इजाफा हो रहा है। साल दर साल आपूर्ति बदलने से विश्वसनीयता पर असर होता है। सन 2015 के ईरान परमाणु समझौते के पहले भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता थे सऊदी अरब, इराक, नाइजीरिया और वेनेजुएला। वर्ष 2016 से ईरान तीन शीर्ष आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया था लेकिन अब वह एक बार फिर नीचे फिसल गया है। यदि अमेरिका और इराक के बीच का तनाव बढ़ता है तो तेल आपूर्ति के एक और बड़े स्रोत के लिए जोखिम उत्पन्न हो जाएगा।

इस बीच 2017 में पहली बार अमेरिकी कच्चा तेल भारत पहुंचा। वह पहले ही छठा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन चुका है। हालांकि चालू वर्ष में इराक के 25 फीसदी की तुलना में उसकी हिस्सेदारी केवल 5.7 फीसदी रही। खबरों के मुताबिक भारत रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने के लिए लंबी अवधि के अनुबंध पर काम कर रहा है। इसके बावजूद पश्चिम एशिया मध्यम अवधि में अहम बना रहेगा। नवंबर तक इस क्षेत्र ने भारत के तेल आयात में 55 फीसदी हिस्सेदारी की। दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक चीन इस क्षेत्र पर महज 43 फीसदी निर्भरता रखता है। विविधता अपनाने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र की घटनाएं सरदर्द साबित होती हैं।

तेल कीमतें और उनका अनुमानित होना भी एक चुनौती है क्योंकि अतीत में तेल आयात बिल में काफी अनिश्चितता देखने को मिली है। इस अनिश्चितता के कारण जीवाश्म ईंधन सब्सिडी या कर राजस्व बजट का निर्धारण करना मुश्किल होता है। वित्त वर्ष 2015 में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी बिल 16.8 अरब डॉलर और वित्त वर्ष 2018 में 9.4 अरब डॉलर था। ऐसे उतार-चढ़ाव औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करते हैं। खासतौर पर उस समय जबकि कच्चे माल की लागत में ऊर्जा की हिस्सेदारी अधिक हो। आयातित गैस कीमतें एक और पहलू शामिल करती हैं। गैस की अधिकता के कारण एशिया में हाजिर बाजार कीमतें 4 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) हो गई हैं। भारत पूर्व अनुबंध के मुताबिक कतर से 85 लाख मिलियन टन गैस 9-10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू की दर पर लेने को बाध्य है। ऐसे में सौदे की शर्तों पर नए सिरे से चर्चा की बात हो रही है। पेट्रोनेट अमेरिकी कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी ले सकती है, ऐसे में टेलूरियन को कम दरों पर 50 लाख टन गैस मिल सकती है। यह कीमत तय करेगी कि भारत की अर्थव्यवस्था किस हद तक गैस आधारित होगी।

तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने में समुद्री सुरक्षा सहयोग की अहम भूमिका है। भविष्य में इसमें स्थिरता और सीमा पार बिजली ग्रिड की सुरक्षा भी शामिल हो सकती है, बशर्ते कि हम सीमा पार बिजली कारोबार शुरू करें। एक एशियाई सुपरग्रिड को लेकर भारी चर्चा चलती रही है। इसकी अपनी अलग तकनीकी और राजनीतिक चुनौतियां और निहितार्थ हैं।

आपूर्ति बाधा कम करने के लिए भारत सामरिक तेल रिजर्व में निवेश करता रहा है। हालांकि सुरक्षित भंडारण की हमारी समझ व्यापक जमीनी बातों से अलग है। बैटरी तकनीक का उदय मौजूद विकल्पों को कई तरह से प्रभावित करेगा। आर्थिक तंत्र के विद्युतीकरण की गति इससे ही निर्धारित होगी। खासतौर पर लाखों सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रम जिनके लिए बिजली की खराब गुणवत्ता चिंता का प्रमुख विषय है। ऊर्जा भंडारण, बिजली के मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को भी प्रभावित करेगा। हाल में सौर ऊर्जा और भंडारण की सफल बोली की दर ताप बिजली के साथ प्रतिस्पर्धी रही जो उत्साहवर्धक है। वैकल्पिक इलेक्ट्रोकेमिकल बैटरी केमिस्ट्री पर इस बात का असर होगा कि हम वितरित बिजली पर कितना भरोसा कर सकते हैं और ग्रिड आधारित व्यवस्था को कितनी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। सामरिक तेल रिजर्व के अलावा भारत को चक्रीय अर्थव्यवस्था और उन अहम खनिजों के सामरिक रिजर्व के बारे में गंभीरता से विचार करना होगा जो विभिन्न ऊर्जा भंडारण कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

ऊर्जा में बदलाव चौथी तरह के जोखिम सामने लाता है जिन्हें वित्तीय रूप से फंसी हुई परिसंपत्ति कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास कंपनियों की बैलेंस शीट पर जीवाश्म ईंधन भंडार के मूल्य को लेकर संदेह उत्पन्न करते हैं। फाइनैंशियल टाइम्स के मुताबिक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने की स्थिति में सरकारी तेल कंपनियों का करीब आधा भंडार बेकार हो जाएगा। कई तेल निर्यातक कंपनियों पर इसका बहुत बुरा असर होगा। उस स्थिति में 13 बड़ी अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों को 360 अरब डॉलर मूल्य का नुकसान होगा।

दुनिया के बड़े निवेशक इस बदलती हकीकत को आकार दे रहे हैं। दिसंबर में 631 गैर अमेरिकी निवेशक जिनके पास 37 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति थी, ने सरकार से कहा कि वह जलवायु संबंधी कदमों को गति दे। गत माह 7 लाख करोड़ डॉलर की सबसे बड़ी परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी ब्लैकरॉक ने कहा कि वह उच्च स्थायी जोखिम वाले निवेश से बाहर निकलेगी।

कोयले के साथ ज्यादा जोखिम है। मौजूदा कोयला भंडार का बमुश्किल चौथाई हिस्सा दो डिग्री सेल्सियस वाली परिस्थिति में जलाया जा सकता है। सन 2011 से अब तक कोयला खनन कंपनियों के मूल्य में 74 प्रतिशत की गिरावट आई है। कोयला उत्पादन बढ़ाने की घोषणाओं के बीच भारत को फंसी परिसंपत्ति के जोखिम का आकलन करना होगा। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ऊर्जा सुरक्षा तकनीक, आर्थिकी या भूराजनीति से प्रभावित हुई है। अब इन सभी मोर्चों पर बदलाव हो रहे हैं। ऊर्जा की मांग भी पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरित हो रही है। पुरानी चिंताएं और नई समस्याएं घुलमिल गई हैं। भारत को आगे रहने की तैयारी रखनी होगी।

(लेखक काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवॉयरनमेंट ऐंड वाटर के सीईओ हैं)

भारत-अमेरिका व्यापार के संदर्भ में बहुत कम सिद्धांत प्रासंगिक

सम सामयिक

टीसीए श्रीनिवास-राघवन

डॉनल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से दोनों पक्षों को कुछ लाभ हो सकते हैं, लेकिन क्या गतिरोध दूर होंगे? इसके जवाब के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत पर नजर डालना जरूरी है। यह वर्ष 1945 के बाद अर्थशास्त्र में सबसे ज्यादा अनुसंधान वाले विषयों में से एक होता था। लेकिन 1970 के दशक में अमेरिकियों की सिद्धांतों में रुचि खत्म हो गई और उन्होंने बाजारों में पकड़ बनाने के लिए साम्राज्यवादी तरीके अपनाए। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री केवल आकंड़ों का विश्लेषण करते हैं।

आंकड़ों के उपयोग अवश्य हैं, विशेष रूप से रणनीति और कार्यनीतियों को दुरुस्त बनाने के लिए। लेकिन ये देशों के बीच व्यापार के पैटर्न की ठीक से व्याख्या नहीं करते हैं और न ही यह बताते हैं कि उन्हें अपने बीच व्यापार को कैसे देखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि आर्थिक सिद्धांत स्थायी माने जाने वाले तर्क पर आधारित होते हैं। लेकिन आंकड़े बदलते रहते हैं। ये आज प्रासंगिक हैं, कल नहीं। इसलिए सिद्धांत की शिक्षाओं को भूलना बहुत बुद्धिमानी नहीं है। ऐसे बहुत कम सिद्धांत हैं, जो विशेष रूप से भारत-अमेरिका के संदर्भ में प्रासंगिक हैं। इनके बारे में पाठकों को जानकारी देना उचित है।

सबसे पहला सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया, जिन्होंने कहा कि महज लाभदायी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी उद्योग होना ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी यानी तकनीकी बढ़त वाले उद्योग होना बेहतर है क्योंकि एक सीमित अवधि में लाभप्रद लेकिन कम प्रतिस्पर्धी उद्योगों के बंद होने से होने वाला आर्थिक नुकसान कारोबार से मध्यम अवधि में प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक होगा।

बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को खारिज करने की कोशिश की है। लेकिन यह काफी हद तक अब भी सही है क्योंकि बहुत से उद्योगों के बंद होने से बेरोजगारी के राजनीतिक परिणामों को स्वीकार करना अहम है। जो देश इन नतीजों को स्वीकार करते हैं, वह अच्छा प्रदर्शन करता है। अमेरिका भी अब तक ऐसा करता आया है। भारत जैसे देशों का भी खराब प्रदर्शन नहीं रहा है।

उसके बाद क्लासिक हेक्चर-ओहलिन सिद्धांत में महत्त्वपूर्ण बात कही गई है। इसने रिकार्डो के प्रतिस्पर्धी लाभ के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इसमें कहा गया कि देश उन उत्पादों का निर्यात करते हैं, जिनमें उनके उत्पादन के भरपूर और सस्ते संसाधनों का इस्तेमाल होता है और उन उत्पादों का आयात करते हैं, जिनमें देश के दुर्लभ संसाधनों का उपयोग होता है। यह साफ नजर आता है, लेकिन यह सफलता के लिए पूरी तरह मुक्त श्रम बाजारों पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि लोगों को कभी भी नियुक्त करने और कभी भी हटाने की प्रणाली को अपनाना है। चुनावी राजनीति इसे मुश्किल बना देती है, इसलिए वे यूरोपीय संघ जैसी कल्याणकारी नीतियों को अपनाते हैं।

इसके बाद 1950 के दशक में वेसली नियोन्टिफ ने हेक्टर-ओहलिन सिद्धांत का परीक्षण किया और अपना लोकप्रिय विरोधाभास पेश किया। निर्यात आंकड़ों के विश्लेषण के बाद उन्होंने पाया कि अमेरिका श्रम संसाधन की अधिक जरूरत वाली चीजों का निर्यात कर रहा है, जहां श्रमिकों की किल्लत और पूंजी की बहुतायत वाला देश है।

इसे लेकर आर्थिक क्षेत्र में तब तक चिंता बनी रही, जब तक किसी ने इसकी व्याख्या नहीं की। इसमें कहा गया कि कुशल श्रम भी पूंजी का एक प्रकार है। अब भारत भी इसका बड़ी मात्रा में निर्यात अमेरिका को करता है।

तीसरा सिद्धांत 1941 में दिया गया। इसे स्टोलपर-सैमुअलसन सिद्धांत नाम दिया गया। इसमें कहा गया है कि अगर वाई के संदर्भ में एक्स की कीमत बढ़ती है तो एक्स के उत्पादन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल साधन का वास्तविक प्रतिफल बढ़ेगा। इसका विपरीत भी होता है। कुछ साल बाद पॉल सैमुअलसन ने इस सिद्धांत को साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत के रूप में फिर से पेश किया। इसमें कहा गया है कि अगर आप पूरी तरह सीमाओं को खोल देते हैं तो श्रम और पूंजी की लागत समान हो जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि क्यों राजनीति इसे रोकती है। अमेरिका में चीनी नाइयों या भारतीय सॉफ्टवेयर कर्मचारियों की किन्हें जरूरत है?

सैमुअलसन ने सिद्धांत दिया कि गैट का दायरा वस्तु एवं शुल्क में कमी से ज्यादा व्यापक होना चाहिए। इसे साम्यवाद के आकर्षण को मात देने के सबसे बेहतर तरीके के रूप में देखा गया। अब यह साफ हो जाना चाहिए कि इन सभी सिद्धांतों का सार यह है कि देश उन चीजों का निर्यात करते हैं, जिन्हें वे सस्ती लागत पर बना सकते हैं और उन चीजों का आयात करते हैं, जिनका वे सस्ती लागत पर नहीं बना सकते हैं। चीन की सफलता इन सिद्धांतों का सबूत है। इससे भारत की नाकामी का पता चलता है।

ऐसे में अब अमेरिका किन चीजों का सस्ती दरों पर उत्पादन करता है और किसी उत्पाद में सबसे ज्यादा किस साधन का इस्तेमाल होता है? यह साधन डॉलर है। अगर कोई देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है तो कारोबारी ताकत हमेशा उत्पादन के भरपूर कारकों से जुड़ी रहती है। इसलिए चीन में श्रम है और अमेरिका में डॉलर है और इन डॉलर के उत्पादन की तकनीक रिकार्डो का सिद्धांत है। दोनों देशों की मिलकर और अलग-अलग तगड़ी कारोबारी ताकत है। भारत में क्या भरपूर है? सही मायनों में कुछ भी नहीं।

भारत के 99 फीसदी श्रमिक अर्द्ध-कुशल या अकुशल हैं, इसलिए इस साधन की बहुतायत का कोई फायदा नहीं है। वहीं देश में जो थोड़े-बहुत कुशल श्रमिक हैं, उनका यह निर्यात करता है। इससे न डॉलर की बहुत अधिक आमदनी होती है और न ही तकनीक खरीद की क्षमता पैदा होती है।

इस तरह भारत लाभप्रद कारोबार की हर आवश्यक शर्त पर खरा नहीं उतरता है। यही वजह है कि भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उपनिवेशवादी शोषण के रूप में देखने के वाम अर्थशास्त्र के प्रभावों को दूर करने के लिए नियो क्लासिकल व्यापार सिद्धांत में एक रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत है।

कानाफूसी

हल्ला बोल

राज्य सभा में सोमवार को ज्यादा कामकाज नहीं हो पाया क्योंकि विपक्षी दल दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर नाराज थे। पहले सदन को अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब यह दोबारा शुरू हुआ तो विपक्षी सदस्य सभापति के आसन के सामने नारेबाजी करने लगे। उपसभापति हरिवंश कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा कि वह संस्कृत विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक पर चर्चा शुरू करें। विपक्षी सदस्यों ने विरोध जारी रखा। बहरहाल, उपसभापति ने सदन की कार्यवाही स्थगित नहीं की। पोखरियाल के बाद भाजपा के सत्यनारायण जटिया ने विधेयक पर बोलना शुरू किया। इस बीच कांग्रेस सदस्य बी के हरिप्रसाद उठे और उन्होंने हल्ला बोल, तड़ीपार पे हल्ला बोल का नारा लगाना शुरू कर दिया। इसके तत्काल बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

बंगाल का गौरव

दिल्ली विधानसभा चुनावों में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की भारी जीत से उत्साहित होकर तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव का प्रचार शुरू करने का निर्णय लिया है। राज्य में निकाय चुनाव भी महज कुछ महीने दूर हैं। ऐसे में राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को एक नया अभियान शुरू किया जिसका शीर्षक है- बंगाल का गौरव ममता। यह अभियान बंगाली अस्मिता और ममता के नेतृत्व पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके साथ ही पार्टी को उम्मीद है कि वह प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उभार को रोक लेगी।

अगले करीब 75 दिन तक तृणमूल कांग्रेस के एक लाख कार्यकर्ता लोगों को यह बताने का काम करेंगे कि क्यों ममता बंगाल के विकास के लिए अहम हैं और प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार रखने में उनकी क्या भूमिका है। दिल्ली में आप की मदद करने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी तृणमूल की सहायता कर रहे हैं।

आपका पक्ष

दिल्ली में मुफ्त पानी का दूसरा पक्ष

राजधानी दिल्ली में मुफ्त बिजली-पानी सुनने में भले ही सुखद और विकासात्मक लगता हो, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल ने इस योजना को बनाते समय कई मुख्य पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया। यह जितना लुभावना है उतना ही नुकसानदेह भी है। पानी मुफ्त होने के बाद दिल्ली वासियों ने जिस तरह से पानी का दोहन शुरू किया है उसके परिणाम स्वरूप जिन जगहों में सीवर नहीं है, वहां की गलियों में पानी जमा होने लगा है जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल होने लगा है। कच्ची कॉलोनियों के लोग पहले ही सीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। उसपर जल जमाव की समस्या विकराल रूप ले चुका है। सवाल यह उठता है कि पानी के दोहन का सबसे बड़ा कारण क्या है। पानी मुफ्त किए जाने के साथ ही कई इलाकों में तेज गति से नए नल भी लगाए गए हैं। वहीं सैकड़ों नल ऐसे हैं जो टूट गए हैं जिससे

पानी बहता रहता है। गलियों में लगाए गए सार्वजनिक नल जिसमें मीटर भी नहीं लगा रहता है उसकी हालत कमोबेश ऐसी ही हो गई है। ऐसे टूटे हुए या खुले हुए नलों में जब पानी आता है तो वह बेकार में बहने लगता है। इससे नल के आसपास या पूरी गली में पानी भर जाता है। सीवर नहीं होने की वजह से ऐसे गलियों में हमेशा पानी जमा

दिल्ली में जलजमाव रोकने के लिए लगातार सीवर की सफाई करने की जरूरत है

रहता है। इसे आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत समझें या फिर सरकार की विफलता, इस समस्या पर सरकार ने गौर नहीं किया है। इसके अलावा हजारों लोगों ने नलों में मीटर नहीं लगाया है और जिन लोगों ने लगाया है वह पानी का इस्तेमाल कम करें या ज्यादा, उन्हें हजारों रुपये तक का बिल थमा दिया जाता है। बिल की गड़बड़ी की जांच पड़ताल के लिए या फिर पानी की बरबादी के लिए विभाग द्वारा किसी अधिकारी को नहीं भेजा जाता है। ऐसे समय में जब पानी की समस्या पूरे देश के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, दिल्ली सरकार को समझना होगा कि ऐसी लापरवाही जनता और सरकार के लिए नुकसानदेह है।

अनुराधा, नई दिल्ली

दिल्ली हिंसा से सबक लेने की जरूरत

दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा से पूरे देश को सबक लेने की जरूरत है। अफवाहों के कारण शुरू हुई हिंसा में अबतक कई लोग मारे जा चुके हैं तथा सैकड़ों लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा को काबू करने की जिम्मेदारी या किसी राज्य की शांति व्यवस्था बनाने रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तथा यहां की पुलिस केंद्र सरकार अथवा गृह मंत्रालय के अधीन है। हिंसा के शुरू होने पर अगर कठोर कदम उठाए गए होते तो शायद हिंसा तीन दिन तक नहीं चलती और जानमाल का नुकसान कम हुआ होता। सोमवार को शुरू हुए संसद सत्र में विपक्षी दलों ने हिंसा के लिए सरकार को घेरा वहीं सत्ता पक्ष ने भी विपक्षी दलों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। लेकिन यह सांप चले जाने पर लकीर पीटने जैसा ही रहा और नुकसान आखिकार आम जनता को ही उठाना पड़ा। अत: ऐसी हिंसा दोबारा नहीं हो इसके लिए लोगों को अफवाह फैलाने वालों को पकड़ कर पुलिस को सौंपना होगा।

संजय सिंह, गाजियाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

सोयाखली निर्यात में 67 फीसदी गिरावट

भाषा
इंदौर, 3 मार्च

प्रसंस्करणकर्ताओं के एक संगठन ने आज अनुमान जताया कि मौजूदा तेल विपणन वर्ष (अक्टूबर 2019-सितंबर 2020) में भारत से सोयाखली निर्यात करीब 67 फीसदी घटकर सात लाख टन रह सकता है। इंदौर स्थित सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सोपा) के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक ने बताया, 'मौजूदा हालात को देखते हुए हमें लगता है कि जारी तेल विपणन वर्ष में देश से सोयाखली निर्यात सात लाख टन के आस-पास रहेगा।' उन्होंने बताया कि सोपा ने पहले अनुमान लगाया था कि मौजूदा तेल विपणन वर्ष में देश से 10 लाख टन सोयाखली का निर्यात हो सकता है। लेकिन इस अनुमान में तीन लाख टन की कटौती की गई है।

पाठक ने कहा, 'देश को सोयाखली के निर्यात में भारी मूल्य प्रतिस्पर्धा का पहले ही सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, प्रसंस्करणकर्ताओं के मन में यह अनिश्चितता भी है कि सोयाखली निर्यात पर मिलने वाला सरकारी प्रोत्साहन एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2020-21 में जारी रहेगा या नहीं।' सोपा के आंकड़ों के मुताबिक पिछले तेल विपणन वर्ष 2018-19 (अक्टूबर 2018-सितंबर 2019) में देश से 21.43 लाख टन का सोयाखली निर्यात किया गया था। चालू तेल विपणन वर्ष में अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 तक देश से 3.12 लाख टन सोयाखली का निर्यात किया गया। यह पिछले तेल विपणन वर्ष की समान अवधि में देश से 13.81 लाख टन के सोयाखली निर्यात के मुकाबले लगभग 77.5 फीसदी कम है। जानकारों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सोयाखली के भाव अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना के इस उत्पाद के मुकाबले लंबे समय से ऊंचे बने हुए हैं। इससे भारतीय सोया खली की मांग पर विपरीत असर पड़ रहा है।

अमेरिका, ब्राजील और अर्जेंटीना की गिनती दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादकों के रूप में होती है। सोया खली वह उत्पाद है जो प्रसंस्करण इकाइयों में सोयाबीन का तेल निकाल लेने के बाद बचा रह जाता है। यह उत्पाद प्रोटीन का बड़ा स्रोत है। इससे सोया आटा और सोया बड़ी जैसे खाद्य उत्पादों के साथ पशु आहार तथा मुर्गियों का दाना भी तैयार किया जाता है।

सरकार ने 530 मिलों को 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा दे रखा है

लक्ष्य का 80 फीसदी होगा पूरा

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 3 मार्च

आपूर्ति में गिरावट के पूर्वानुमान के कारण पिछले कुछ सप्ताह से वैश्विक स्तर पर चीनी के दामों में हुए तेज इजाफे की वजह से भारत चीनी सत्र अक्टूबर 2018 से सितंबर 2020 के लिए आवंटित निर्यात कोटे का 80 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य हासिल कर सकता है।

सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फैली 530 मिलों को 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा आवंटित किया हुआ है। यह इन मिलों की पेराई क्षमता और अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटे (एमएईक्यू) के तहत चालू सीजन के इनके पिछले रिकॉर्ड पर निर्भर करता है। इस कोटे में से चीनी मिलें पहले ही संयुक्त रूप से लगभग 35 लाख टन का अनुबंध कर चुकी हैं और निर्यात के लिए अपने कारखानों से तकरीबन 23 लाख टन की ढुलाई कर चुकी हैं।

देश से निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ चीनी की घरेलू अधिकता में कमी लाने के लिए सरकार ने निर्यात करने वाली मिलों को 6,00,000 टन कोटे का फिर से आवंटन किया था। यह कोटा उन मिलों से वापस लिया गया था जिन्हें कोटे की मात्रा आवंटित तो की गई थी लेकिन वे इसका निर्यात नहीं कर पाई थीं।

> कोरोनोवायरस के डर से पिछले कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दामों में नरमी आई

भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा, 'हम इस साल 50 लाख टन से अधिक चीनी निर्यात कर लेंगे जो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। यह देखते हुए कि सरकार काफी सक्रिय है, निर्यात के लिहाज से इस साल चीनी मिलों का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में बेहतर रहेगा।'

पिछले साल आवंटित इस 50 लाख एमएईक्यू में से चीनी मिलें 38 लाख टन निर्यात कर पाई थीं। वर्मा ने कहा, 'इस साल अधिक मात्रा में चीनी निर्यात कर पाने के तीन प्रमुख कारण हैं। पहला, निर्यात की मात्रा का अवंटन प्राप्त करने वाली इन 530 मिलों में से बहुत-सी मिलों को नकदी प्रवाह, कच्ची चीनी की उपलब्धता और पिछले साल के लिए सरकार की ओर से जारी सब्सिडी अटकने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप आवंटित कोटे में कमी आई है। दूसरा, सरकार ने गैर-निर्यातित मात्रा का तीन हिस्सों में फिर से आवंटन करने का फैसला किया है यानी जनवरी, मार्च और जून की अवधि में। तीसरे, प्रति वर्ष 5,00,000 से 8,00,000 टन के बीच निर्यात करने वाली काकीनाडा की एक बड़ी रिफाइनरी को इस साल तकनीकी कारणों से निर्यात के लिए लाइसेंस नहीं मिला है। इन सब बातों को देखते हुए हम इस साल 50,00,000 लाख टन से ज्यादा चीनी निर्यात का अनुमान लगा रहे हैं।'

इस बीच कोरोनोवायरस के डर से काम बंदी के बीच मांग में कमी की वजह से पिछले कुछ दिनों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी के दामों में नरमी आई है। सत्र के शीर्ष स्तर पर जाने के बाद बेंचमार्क इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज (आईसीई) पर मई में डिलिवरी वाली चीनी का वायदा भाव पिछले दो हफ्तों में घटकर फिलहाल प्रति पौंड 13.83 सेंट के स्तर पर चल रहा है, जबकि पहले इस सत्र में इसका भाव प्रति पौंड 15.12 सेंट के शीर्ष स्तर पर था। कोरोनावायरस के फैलने से सभी जिंसों में आई गिरावट के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि भारत में पिछले साल के बचे तकरीबन एक करोड़ टन के स्टॉक के साथ-साथ अधिक उत्पादन से चीनी के दामों पर दबाव रहा है जो हाजिर बाजार में 31 से 32 रुपये प्रति किलोग्राम के दायरे में सीमित रहे हैं। इस बीच इस्मा ने आज एक बयान में कहा कि देश में सक्रिय 453 मिलों ने अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 के बीच की अवधि में संयुक्त रूप से 1.948 करोड़ टन चीनी उत्पादन किया है। पिछले साल की इसी अवधि में दर्ज 2.493 करोड़ उत्पादन की तुलना में इसमें 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

सरकार ने दोबारा आवंटन किया था कोटा

- निर्यात बढ़ाने और चीनी की घरेलू अधिकता में कमी लाने के लिए सरकार ने 6 लाख टन कोटे का फिर से आवंटन किया था
- यह कोटा उन मिलों से वापस लिया गया था जिन्हें कोटे की मात्रा आवंटित तो की गई थी लेकिन वे इसका निर्यात नहीं कर पाई थीं

वैश्विक वायदा भाव

दिन	सेंट/पौंड
7 फरवरी	14.69
10 फरवरी	14.74
11 फरवरी	15.04
12 फरवरी	15.06
13 फरवरी	14.78
14 फरवरी	14.55
18 फरवरी	14.87
19 फरवरी	15.08
20 फरवरी	14.94
21 फरवरी	15.12
24 फरवरी	14.73
25 फरवरी	14.74
26 फरवरी	14.54
27 फरवरी	14.20
28 फरवरी	14.14
2 मार्च	13.81
3 मार्च	13.83

स्रोत- ब्लूमबर्ग, संकलन- बीएस रिसर्च

कोरोनावायरस का असर बासमती चावल निर्यात पर

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 3 मार्च

कई स्थानों पर खरीद सुचारु रूप से नहीं होने की शिकायत के अलावा रिकॉर्ड घरेलू फसल के साथ-साथ निर्यात में गिरावट आ रही है। दूसरी तरफ भारत से किया जाने वाला चावल निर्यात पहले ही अमेरिका-ईरान के बीच गतिरोध की आंच झेल रहा है। इसके अलावा ईरान की ओर से कोरोनावायरस के प्रकोप से कई मौतों की खबर आने के बाद निर्यात को और ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पश्चिम एशिया का यह देश भारतीय बासमती के शीर्ष अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में से एक है। वर्ष 2019-20 के दौरान 11.7 करोड़ टन से अधिक के जोरदार धान उत्पादन के साथ ही निर्यात के इस निराशाजनक परिदृश्य के कारण भारतीय निर्यातकों को अब बड़े नुकसान की आशंका नजर आ रही है। पांच साल के औसत उत्पादन 10.78 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान उत्पादन 96.7 लाख टन अधिक रहा है। वर्ष 2010 और 2019 के बीच लगभग 14 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज करने वाले चावल उत्पादन को नकारात्मक भू-राजनीति, सरकार द्वारा अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और कड़े व्यापारिक मानदंडों के कारण नुकसान पहुंचा है। बाजार के नकारात्मक परिदृश्य के परिणामस्वरूप एक्सचेंजों पर बासमती के दामों में गिरावट का रुख रहा है।

कोरोनावायरस फैलने से जिंस एक्सचेंज आईसीईएक्स पर सबसे ज्यादा बिक्री वाली बासमती किस्म (पीबी1121) का भाव फिसलकर 3,030 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच चुका है। हालांकि धान के हाजिर बाजार में लगातार गिरावट देखी गई है। वायरस प्रकोप के बाद ईरान ने भारतीय बासमती की खेप रोक दी हैं। इस वजह से इस वित्त वर्ष में निर्यात में 18 से 20 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है। केडिया एडवाइजरी के निदेशक अजय केडिया ने कहा कि भारत के बासमती निर्यात में ईरान और पश्चिम एशिया के बाकी देशों का योगदान सबसे अधिक रहता है। देश के निर्यात में इनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक रहती है।

कोहिनूर फूड्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक गुरनाम अरोड़ा ने कहा कि निर्यातकों के लिए कोरोनावायरस चिंता का सबसे बड़ा विषय है तथा अब ईरान में ऐसे मामलों की खबर आने से स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। इस प्रकोप का प्रभाव पहले ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यात्राओं पर दिखाई दे रहा है।

भारतीय निर्यातकों को अब बड़े नुकसान की आशंका नजर आ रही

उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह में हालात में क्या बदलाव आता है, इस संबंध में चावल निर्यातकों ने 'इंतजार करो और देखो' का दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। कोहिनूर फूड्स चावल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस बीच मुंबई के चावल व्यापारी देवेंद्र वोरा निकट अवधि में उद्योग की संभावनाओं को लेकर निराश हैं। उनका कहना है कि बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।

वोरा ने कहा कि विभिन्न बाहरी और आंतरिक कारकों की वजह से बाजार में गिरावट जारी है और हम इस बात की केवल आशा ही कर सकते हैं कि अगले एक या दो महीने में स्थिति में सुधार होगा। इससे पहले उन्होंने सुझाव दिया था कि भारतीय निर्यातकों को नुकसान से कुछ हद तक बचाने के लिए केंद्र को ब्राजील के लिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए जो चावल और गेहूं का बड़ा उपभोक्ता देश है। खास तौर पर ईरान को किया जाने वाला बासमती निर्यात वर्ष 2018-2019 में 1.5 अरब डॉलर का रहा। भारतीय चावल निर्यात में ईरान का योगदान 25 प्रतिशत रहता है। अमेरिका स्थित व्यापारिक वित्तीय कंपनी ड्रिप कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर चावल निर्यात में गिरावट देखी गई है। भू-राजनीतिक तनाव की वजह से पश्चिम एशिया की तरफ से बड़ी गिरावट सामने आई है। ड्रिप कैपिटल के सह-संस्थापक और सह-मुख्य कार्याधिकारी पुष्कर मुकेवर ने कहा कि खेपों में 22 प्रतिशत की गिरावट को देखते हुए सालाना आधार पर सबसे बड़े निर्यात बाजार ईरान के साथ निर्यात अब तक निराशाजनक दिख रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 25 प्रतिशत है। हालांकि देश की निर्यात बास्केट में चावल का योगदान केवल दो प्रतिशत ही रहता है।

भारत से 13 थोक दवाओं के निर्यात पर रोक

चीन से आपूर्ति पर पड़ रहे असर को देखते हुए दवा निर्यातकों को लेनी होगी वाणिज्य मंत्रालय से एनओसी

सोहिनी दास

कोरोनावायरस का प्रकोप दुनिया भर में फैलने और इससे मुख्य रूप से प्रभावित चीन से आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच भारत ने घरेलू बाजार में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 13 सक्रिय औषधि-निर्माण सामग्री (एपीआई) और उनसे बनी दवाओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि पैरासिटेमॉल, टिनिडेजोल, मेट्रोनाइडेजोल, विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एसिक्लोविर एवं प्रोगेस्टोरोन जैसी 13 एपीआई और इनसे बनने वाली दवाओं के निर्यात को सीमित करने का आदेश दिया है।

हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह साफ किया कि इन दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। अधिकारी ने कहा, 'इन दवा सामग्रियों एवं निर्मित दवाओं के निर्यात के पहले निर्यातकों को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि इन दवाओं को बड़े पैमाने पर बाहर न भेजा जाए और देश में उनकी उपलब्धता बनी रहे।' इसके अलावा यह एक अस्थायी कदम भी है। अधिकारी ने कहा, 'चीन से औषधि सामग्रियों की आपूर्ति होने लगी है लेकिन अब भी हुबेई प्रांत में मौजूद कारखाने सामान्य स्थिति में नहीं आ पाए हैं। इस वजह से सरकार ने एहतियात बरतते हुए इन औषधि सामग्रियों के निर्यात को सीमित रखने का फैसला किया है। हालात सामान्य होते ही हम इन पाबंदियों को हटा लेंगे।'

हालांकि मुंबई स्थित एक औषधि फर्म के प्रबंध निदेशक ने कहा कि इस कदम से व्यावहारिक स्तर पर इन 13 एपीआई एवं उनकी दवाओं का निर्यात कुछ समय के लिए रुक जाएगा। इस कंपनी अधिकारी ने कहा, 'डीजीएफटी की अधिसूचना में आईटीसी निर्यात नीति 2018 की दूसरी अनुसूची का जिक्र है जो प्रतिबंधित उत्पादों से संबंधित है। संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना एक चार-स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें कम-से-कम 30-45 दिन लग जाएंगे।' करीब एक महीने तक इन दवाओं का निर्यात अवरुद्ध रहेगा। इंडियन फार्मास्युटिकल अलायंस (आईपीए) के महासचिव सुदर्शन जैन का कहना है कि दवा निर्यातक स्थिति स्पष्ट होने के लिए इन पाबंदियों पर अमल से संबंधित ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं।

औषधि विभाग ने चीन में घातक वायरस कोविड-19 के प्रसार की खबरें आने के साथ ही हालात की समीक्षा के लिए एक समिति बनाई थी। समिति ने 12 औषधि निर्माण सामग्रियों के निर्यात पर रोक लगाने की सिफारिश की थी जिसके बाद औषधि विभाग ने डीजीएफटी को इससे अवगत कराया था। लेकिन फरवरी के अंत में नीति आयोग, सरकारी विभागों एवं दवा उद्योग प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह तय हुआ था कि तत्काल इस तरह की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। औषधि उद्योग का दावा है कि घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए देश में इन सामग्रियों का पर्याप्त भंडार मौजूद है।

जीएसके फार्मास्युटिकल के प्रबंध निदेशक ए वैधीश के मुताबिक, फिलहाल सरकार आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं को लेकर सतर्क है और भारत में इस घातक वायरस का प्रकोप बढ़ने पर इस फैसले से देश को मदद मिलेगी।

दवा निर्यात संवर्द्धन परिषद का अनुमान है कि भारत चालू वित्त वर्ष में 2018-19 के अपने प्रदर्शन को पीछे छोड़ देगा। अप्रैल-दिसंबर 2019 के दौरान औषधि निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2018 की तुलना में 11.5 फीसदी दर से बढ़ा है। खासकर दिसंबर तिमाही में तो इसने 14.6 फीसदी की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। इस साल भारत से कुल औषधि निर्यात 22 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। करीब 40 अरब डॉलर के आकार वाले भारतीय फार्मा उद्योग में आधा हिस्सा निर्यात का है।

कैडिला हेल्थकेयर के चेयरमैन पंकज पटेल ने हाल ही में कहा था कि दवाओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना कोई समाधान नहीं है क्योंकि इससे निर्यात बाजार में देश की छवि पर असर पड़ता है।

औषधि उद्योग का दावा है कि घरेलू जरूरतों के लिए देश में सामग्री का पर्याप्त भंडार है

...जटिल हालात

- चीन से औषधि सामग्रियों की आपूर्ति होने लगी है लेकिन हुबेई प्रांत में मौजूद कारखाने सामान्य स्थिति में नहीं आ सके हैं
- सरकार एहतियात के तौर पर इन औषधि सामग्रियों के निर्यात को सीमित कर रही है
- अधिकारियों ने स्पष्ट किया, दवाओं के निर्यात पर नहीं है प्रतिबंध

मोदी के अकाउंट पर महिलाओं की दास्तां

नेहा अलावधी और अर्चिस मोहन

मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट पर छाएंगी महिलाओं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वह सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार कर रहे हैं और इसके ठीक एक दिन बाद ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इस रविवार महिलाएं 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के मौके पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट करेंगी। मंगलवार को मोदी ने अपने अलग सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया, 'इस महिला दिवस (8 मार्च) पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट ऐसी महिलाओं को सौंप दूंगा जिनका जीवन और कार्य हमें प्रेरित करते हैं। इससे लाखों लोगों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। क्या आप ऐसी महिला हैं या आप इसी तरह की किसी प्रेरणा देने वाली महिला को जानती हैं? 'हैशटैग शीइन्सपायरअस' के साथ ऐसी कहानियां हमसे साझा करिये।'

हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि ये महिलाएं कौन होंगी लेकिन उनके फॉलोअर ने सुझाव दिया कि ऐसी महिलाओं में सामूहिक बलात्कार पीड़िता निर्भया की मां आशा देवी, इन्फोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति और छोटे शहरों तथा कस्बे की वैसी महिलाएं हो सकती हैं जिन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी से जुझने में अदम्य साहस का परिचय दिया है। इसके अलावा खिलाड़ियों में जनवरी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से जुड़ने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इस साल पद्म विभूषण सम्मान पाने वाली मुक्केबाज एम सी मैरी कॉम के नाम का सुझाव भी दिया गया। सोमवार की रात को जब प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया छोड़ने पर विचार करने का संदेश पोस्ट किया तब ट्विटर पर काफी हलचल मच गई। उनके इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री को ट्विटर पर फॉलो करने वालों की तादाद में करीब 10,000 का इजाफा हो गया और मंगलवार तक उनके फॉलोअर की तादाद 5.34 करोड़ हो गई जबकि उनके फेसबुक पन्ने को एक दिन में 20,000 से अधिक लाइक मिले।

मंगलवार को एक बयान में सरकार ने कहा कि इसके कई मंत्रालयों ने रविवार को महिला दिवस के मौके के लिए अभियान की शुरुआत की है। इनमें महिला एवं बाल विकास, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मानव संसाधन विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास, आवासीय एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, वित्त, रक्षा एवं गृह मंत्रालय शामिल हैं।

इस अभियान में सात थीम पर चर्चा होगी जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, महिला सशक्तिकरण, कौशल एवं उद्यमशीलता, खेलों में सहभागिता, शहरी एवं ग्रामीण महिलाएं तथा खेती को शामिल किया गया है। 1 से 7 मार्च तक दूरदर्शन पर महिला केंद्रित फिल्में और कई विशेष शो प्रसारित किए जाएंगे।

सरकार इस मौके पर भी यह दर्शाएगी कि महिला केंद्रित योजनाओं मसलन 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, सौभाग्य और मुद्रा योजना से महिला सशक्तिकरण में कितनी मदद मिली है। 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) घोषणापत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के बेहतर मौके का वादा किया गया था। इसमें कहा गया था कि सरकारी खरीद में 10 फीसदी वस्तुएं उन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) से ली जाएंगी जिनके कर्मचारियों में कम से कम 50 फीसदी महिला कर्मचारी हों।

कोरोना: निगरानी में इंडिगो के चालक दल सदस्य

अनीश फडणीस

सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने इटली, जापान और कोरिया में दी जाने वाली विमान सेवाओं में कटौती की है जबकि इंडिगो ने विमान चालक दल के चार सदस्यों को घर में निगरानी में रखा है ताकि कोरोनावायरस के प्रसार की जांच की जा सके। विमानन कंपनी ने ऐसे वक्त पर विमान सेवाओं में कटौती का फैसला किया है जब सरकार ने इटली, जापान और कोरिया के नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है। इससे पहले सरकार ने नागरिकों को चेतावनी जारी की थी कि वे इन देशों में गैर-जरूरी यात्रा न करें। इसके अलावा हवाईअड्डों पर भी 12 देशों से आ रहे यात्रियों की स्वास्थ्य जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है।

इन प्रतिबंधों की वजह से यात्रियों की तादाद में भारी कमी देखी जा रही है क्योंकि ग्राहक अपनी यात्रा की योजना रद्द कर रहे हैं। टोक्यो में विमान सेवा हर हफ्ते में पांच के बजाय चार दफा ही कर दी गई है जबकि मिलान, सोल और रोम में एक हफ्ते में तीन या चार फ्लाइट के बजाय महज दो फ्लाइट की सेवाएं ही दी जा रही हैं। इसी तरह एयर इंडिया भी मक्का-मदीना की यात्रा टलने के बाद बोइंग 747 और बोइंग 777 के बजाय सऊदी अरब के लिए एक छोटे एयरबस ए320 विमान के संचालन की योजना बना रही है।

वहीं इंडिगो ने चालक दल के चार सदस्यों को निगरानी में रखा है क्योंकि वे तेलंगाना के उस व्यक्ति के संपर्क में आए होंगे जिसमें कोरोनावायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस व्यक्ति ने 20 फरवरी को दुबई से बेंगलूरु इंडिगो के विमान में यात्रा की थी। इंडिगो ने एक बयान में कहा, 'हवाईअड्डा स्वास्थ्य संगठन (एपीएचओ) के निर्देशों के मुताबिक केबिन क्रू के चार सदस्यों को निगरानी में रखा गया है और हम एपीएचओ के दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा कोरोनावायरस से प्रभावित क्षेत्रों में विमान संचालित करने वाले क्रू सदस्यों के लिए रोकथाम उपाय कर रहे हैं।'

एयर इंडिया ने भी 25 फरवरी को वियना-दिल्ली की फ्लाइट के चालक दल के सदस्यों को 14 दिनों तक अपने घर में अलग रहने को कहा जब दिल्ली के एक यात्री में संक्रमण की पुष्टि हो गई।

बेहतरीन रेस्तरां और खानसामों की अब देसी रैंकिंग

पवन लाल

जब एक प्राइवेट इक्विटी निवेशक, एक दिग्गज पाक कला पत्रकार और दो मिशलिन सितारों वाले एक पुरस्कार विजेता भारतीय खानसामा एक साथ मिलकर कोई उद्यम शुरू करें तब आखिर क्या मुमकिन होगा? इसका जवाब यह है कि इस मेल से भारतीय खानसामों के लिए मिशलिन स्टार रैंकिंग एक अपना भारतीय संस्करण शुरू हो रहा है। एवरस्टोन ग्रुप के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर सेन खुद भी भारतीय खाने के बड़े प्रशंसक हैं और उन्होंने 'कलिनरी कल्चर' जैसा एक मंच तैयार किया है जिसका मकसद मिशलिन रैंकिंग की तर्ज पर ही रेस्तरां और खानसामों को 'फूडस्टार्स' जैसी रैंकिंग देना है।

'मिशलिन गाइड्स' किताबों की एक सीरीज हैं जिसे फ्रांस की टायर कंपनी ने कई दशकों तक प्रकाशित किया और स्टार रेटिंग के जरिये अवॉर्ड दिया जाता है जो एक से अधिकतम तीन स्टार तक होता है। स्टार मिलने या खोने से यूरोप और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के रेस्तरां की सफलता पर काफी असर पड़ सकता है। सेन कहते हैं, 'भारतीय खानपान अभी मुख्यधारा में शामिल नहीं हैं। इटली की पाक कला, जापानी और पेरू के व्यंजन भी मुख्यधारा में शामिल किए जा चुके हैं लेकिन दूसरे देशों के खानपान की तरह आप दुनिया भर में भारतीय व्यंजन का लुत्फ नहीं उठा पाते। यह एक ऐसी पहल है जिससे इसमें बदलाव आएगा। भारत में फिलहाल तीन ही बड़ी चीज है और वह है क्रिकेट, बॉलीवुड और खानपान।'

उनका कहना है कि इस पहल के लिए शुरुआती स्तर पर 50 लाख डॉलर तक का निवेश किया जाएगा और भारतीय खानसामों के लिए 'फूडस्टार' रैंकिंग दी जाएगी जो एक ऐसी पेशेवर रैंकिंग होगी जिस पर किसी विज्ञापन, वोट या लोकप्रियता का प्रभाव नहीं होगा।

खाने की जगहों का कैसा दायरा

शहर	रेस्तरां की तादाद
दिल्ली	95, 287
मुंबई	87,650
बेंगलूरु	42, 307
कोलकाता	38,838
कुल	264, 182

स्रोतः एनआरएआई इंडिया फूड सर्विस

कलिनरी कल्चर के समीर जैन, वीर सांघवी, गगन आनंद, राज सांघवी (बाएं से)

सेन की कंपनी एवरस्टोन समूह ने भारत में पहले भी बर्गर किंग की फंडिंग की थी और उनका कहना है कि इस तरह की रैंकिंग और इसकी प्रक्रिया भी ग्रैमी अवॉर्ड तथा ऑस्कर के नामांकन की प्रक्रिया व संकलन का पूरा अध्ययन करने के बाद तैयार की गई है। ये रैंकिंग वैसे पेशेवर तय करेंगे जो व्यापार को अच्छी तरह समझते हैं और इसमें शेफ गगन आनंद भी शामिल होंगे जो कलिनरी कल्चर के लिए सलाहकार की भूमिका में होंगे। क्या यह मंच किसी खास तरह की पाककला को लेकर पक्षपाती होगा? आनंद कहते हैं, 'हम उन खानसामों को बढ़ावा देने के लिए यहां नहीं हैं जो पहले ही अपनी कंपनियों के बॉस हैं या फिर जो रियालिटी शो चला रहे हैं। खानसामे के खाना पकाने के आइडिया की रैंकिंग होगी और उन बेहतरीन शेफ को बढ़ावा दिया जाएगा जो अपनी कला के प्रति ईमानदारी बरतते हैं भले ही वे कुछ भी पकाते हों। मेरा ताल्लुक कोलकाता से हैं और मैंने भी बतौर पेस्ट्री शेफ, प्रशिक्षण देने के साथ शुरुआत की।' आनंद का कहना है कि प्रत्येक खानसामे के निजी सफर के साथ ही प्रभाव में अंतर होगा लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसका स्वाद कैसा है। आनंद कहते हैं, 'भारत और भारतीय खाने से जुड़ा संबंध ही खत्म हो रहा था लेकिन अब इसके जरिये जुड़ाव की पूरी गुंजाइश है।'

कलिनरी कल्चर वैश्विक स्तर की रैंकिंग वाले खानसामों को भारत बुलाने के साथ ही स्थानीय खानसामे को विदेश ले जाने की पहल भी करेगा ताकि वे वैश्विक रैंकिंग वाले रेस्तरां में काम कर सकें। कलिनरी कल्चर में आनंद की भूमिका अहम होगी। इस उद्यम के कार्यकारी अध्यक्ष वीर सांघवी कहते हैं कि 'फूडस्टार्स' कठिन प्रक्रिया के जरिये दिया जाएगा जिसमें दि एकेडमी भी शामिल है जो पाककला विशेषज्ञ, खाद्य समीक्षक, उद्योग से जुड़ी शख्सियतों और लेखकों की 50 लोगों की एक टीम है। सांघवी कहते हैं, 'यह पहल लजीज खाने से जुड़ी है और इसका दायरा बड़े रेस्तरां या पांच सितारा तक ही सीमित नहीं है। इसमें ढाबा और सामान्य रेस्तरां भी शामिल होंगे।'

हालांकि कलिनरी कल्चर ने अलग से 'स्ट्रीट फूड सुपरस्टार्स' लॉन्च किया है जो देश में स्ट्रीट फूड वेंडरों को दिया जाने वाला पहला पुरस्कार होगा। ऐप और वेबसाइट पर भी कलिनरी कल्चर की ऑनलाइन मौजूदगी होगी और दिलचस्प बात यह है कि यह बिल्कुल मुफ्त और विज्ञापन से मुक्त होगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड सोशल एक्सीलेंस अवॉर्ड

सामाजिक सरोकारों के पहरुओं को मिला सम्मान

पृष्ठ 1 का शेष

माधवन को उस बात के लिए सम्मानित किया गया जो हर लोकतंत्र के लिए जरूरी है। उन्होंने नेताओं और मतदाताओं को जागरूक बनाने में मदद की। निर्णायक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों में विजेता का चयन करने से पहले कई मानकों पर व्यापक चर्चा की। रामदुरई ने कहा, 'विजेताओं का चयन आसान नहीं था।' निर्णायक मंडल में इस बात पर व्यापक सहमति थी कि काम का असर दिखना चाहिए और इसी बात से विजेताओं के चयन में मदद मिली। रामदुरई की अगुआई वाले निर्णायक मंडल में सोशल सेक्टर की जानी मानी हस्तियां शामिल थीं। इनमें बैंस कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के चेयरमैन अमित चंद्रा, गिवइंडिया के निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी अतुल सतीजा, प्रथम की सह संस्थापक फरीदा लांबे और इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के संस्थापक-निदेशक लुई मिरांडा शामिल थे। बिज़नेस स्टैंडर्ड अवॉर्ड्स फॉर सोशल एक्सीलेंस कॉरपोरेट, एंटरप्राइजेज और व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा समाज में सार्थक बदलाव के लिए किए जाने वाले अहम प्रयासों को दिया जाता है। ये पुरस्कार हमेशा सोशल सेक्टर के कुछ सर्वश्रेष्ठ नामों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस साल खासकर सोशली अवैयर कॉरपोरेट श्रेणी में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा देखने को मिली। लेकिन निर्णायक मंडल ने एलटीएफएच और डिजिटल साक्षी पर मुहर लगाई। एलटीएफएच के सीईओ दीनानाथ दुभाषी ने कहा, 'कम आय वाले समुदायों को सशक्त बनाने के सिलसिले में डिजिटल फाइनैंस के पूरे सफर में डिजिटल वित्तीय समावेशन अभी भी ग्रामीण समुदायों के लिए कठिन बना हुआ है, खासतौर पर महिलाओं के लिए।' डिजिटल साखी कार्यक्रम (वित्त वर्ष 2017-1708) ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल वित्तीय साक्षरता के माध्यम से सशक्त बनाना चाहता है और उनमें नेतृत्त्व के लिए जरूरी गुण शामिल करना चाहता है। इसका लक्ष्य है अच्छी तादाद में ऐसी महिलाओं की फौज खड़ी करना जो उद्यमी हों और अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम हों।

दुभाषी ने कहा कि कार्यक्रम के शुरुआती वर्षों का एक बड़ा हासिल यह था कि महिलाओं को वित्तीय मामलों में अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उन्हें नेतृत्त्व और विश्वास संपन्न बनाने के साथ-साथ इंटरनेट और मुद्रा संबंधी ज्ञान देना भी उतना ही आवश्यक है। सामाजिक क्षेत्र के तमाम अन्य पहलुओं की तरह आवश्यकता यह है कि अधिकाधिक प्रभाव छोड़ने के लिए सामुदायिक रुख अपनाया जाए। इस पहल ने न केवल उद्यमियों में भरोसा पैदा किया बल्कि इसने समुदाय के लिए रोल मॉडल भी तैयार किए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है।

काम के असर के हिसाब से विजेताओं के चयन में मिली मदद

रामादुरई ने कहा कि जूरी ने एलटीएफएच के काम के आकार और प्रभाव, लैंगिक विविधता, ग्रामीण प्रभाव, ग्रामीण उपस्थिति और भविष्य में इसका आकार बढ़ाने की संभावना आदि को खासतौर पर रेखांकित किया।

जूरी के निहाल और श्यामा कविरत्ने द्वारा संचालित सेंट ज्यूड इंडिया चाइल्ड केयर सेंटर पर ध्यान देने के लिए भी प्रभाव बहुत बड़ी वजह रहा। इन सेंटर को सोशल एंटरप्राइज ऑफ द इयर का पुरस्कार मिला। सेंट ज्यूड सेंटर घर से दूर एक घर की तरह है। यह उन परिवारों के लिए है जो कैंसर के इलाज के लिए अपने बच्चों के साथ बड़े शहर में जाते हैं। सन 2006 में एक सेंटर और 8 परिवारों के साथ शुरुआत करने के बाद आज यह 39 सेंटर चलाता है और देश के 9 शहरों में 500 परिवारों की सेवा करता है।

निहाल कविरत्ने कहते हैं, 'बीते 14 वर्षों में इन केंद्रों में 20,000 से अधिक लोग आए और उन्होंने (परिवारों और बच्चों) 8 लाख रातें चैन के साथ गुजारीं।' इस पहल के बारे में वह कहते हैं, '27 जनवरी 2006 को मुझे टाटा मेमोरियल अस्पताल में बाल कैंसर दिवस कार्यक्रम में मंच पर बुलाया गया था। मेरे हाथ में माइक था और सामने नन्हें चेहरों का सागर लहरा रहा था, सारे गंजे थे, उन्होंने मास्क पहने थे, उनके हाथों में आईवी पोर्ट लगी थी, वे प्रसन्न थे लेकिन उन्हें किसी चीज की उम्मीद थी। मैंने अचानक ही उनसे वादा किया कि किसी गांव या छोटे कस्बे से अपने मां-बाप के साथ इलाज के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में आने वाले किसी बच्चे को सड़क पर दिन नहीं काटने होंगे।' वह कहते हैं कि उनके मित्र और परिजन पहले तो भौंचक्के रह गए लेकिन फिर वे उनकी मदद में जुट गए। निर्णायक मंडल ने कहा कि इस तरह के संस्थान न केवल बीमारी से लड़ने बल्कि इसके लेकर बने डर एवं चेतावनी भरे माहौल को भी दूर करने में मददगार होंगे। कविरत्ने के लिए सफर तो अभी बस शुरू ही हुआ है। उनका मानना है कि एक ऐसा समय आएगा जब किसी गांव या छोटे कस्बे के किसी भी बच्चे को कैंसर के उपचार के लिए बड़े शहर में आने पर सड़कों पर रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा।काम को लेकर ऐसी ही प्रतिबद्धता एवं समर्पण एम आर माधवन में भी नजर आता है जिन्हें पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के लिए वर्ष का सामाजिक उद्यमी चुना गया है। माधवन देश में लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं। इसके लिए वह लोकतांत्रिक संस्थानों को मदद देने के साथ ही राजनीतिक समूहों के बीच जागरूकता पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। माधवन ने अपनी इस संस्था की शुरुआत से जुड़ा प्रसंग सुनाते हुए कहा, 'आईसीआईसीआई सिक्योरिटिज में काम करते समय मैं प्रथम के साथ वॉलंटियर से जुड़ा था और उसी समय व्यापक बदलाव लाने में अंशदान के लेकर रुचि जगी।' इसी प्रेरणा ने एक वित्त पेशेवर को लोकतांत्रिक मूल्यों की आवाज बुलंद करने वाला बना दिया।

लोकतंत्र केवल चुनाव प्रक्रिया या एक संस्था से ही नहीं जुड़ा है। यह अदृश्य धागों का एक गुच्छा है जिन्हें सावधानी से देखभाल की जरूरत होती है और जागरूक एवं मुखर नागरिक इसकी जान होते हैं। माधवन की संस्था पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाई है। सांसदों को मदद देने के अलावा यह संस्था युवाओं को कानून निर्माण एवं लोक नीति के सबक सीखने के लिए फेलोशिप भी देती है।

माधवन के लिए यह सफर चुनौतियों से भरा रहा है। जिन दो विदेशी फाउंडेशनों से इसका करार था उन्हें सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई तो संस्था के पास फंड की भारी किल्लत हो गई थी। माधवन ने कहा, 'हालांकि उसी समय कई भारतीय परोपकारी हमारी मदद के लिए आगे आ गए। फिर नौ वर्षों से हमारा सिलसिला जारी है।'